रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED NoD. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 18, 1973/श्रावण 27, 1895

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 18, 1973/SRAVANA 27, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1973

का० आ० 2324—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए गोवा, दमण और दीव विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 7—टीविम सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री प्रभु रविन्द्र पुरुषोत्तम, टीविम, बरडेज, पणजी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री प्रभु रविन्द्र पुरुषोत्तम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० गोवा-वि०स०/7/72 (3)

वी० एन० भारद्वाज, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 10th July, 1973

S.O. 2324.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Prabhu Ravindra Purushottam, of Tivim, Bardez, Panaji, a contesting candidate for general election to the Goa, Daman and Diu Legislative Assembly from 7—Tivim assembly constituency, held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Electoin Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Prabhu Ravindra Purushottam to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GOA-LA/7/72 (3)]

B. N. BHARDWAJ, Secy

आदेश

का० आ० 2325. —यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1973 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 113 थासरा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पटेल जसभाई नाथभाई, रानिया, तालुक थासरा, जिला कैरा, गुजरात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पटेल जसभाई नाथभाई को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० गुज०वि०स०/113/72 (26)]

ORDER

S.O. 2325.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Patel Jashbhai Nathabhai, Rania, Taluka Thasra, District Kaira, Gujarat, a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Gujarat Legislative Assembly from 113-Thasra constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Patel Jasbhai Nathabhai to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this Order.

[No. GJ—LA/113/72/(26)]

आदेश

का० आ० 2326.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 113 थासरा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री वाघेला छगनभाई भूपतभाई, थासरा, तालुक थासरा जिला कैरा, गुजरात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री वाघेला छगनभाई भूपतभाई को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० गुज०-वि० स०/113/72 (27)]

ORDER

S.O. 2326.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Waghela Chhaganbhai Bhupatbhai, Thasra, Taluka Thasra, District Kaira, Gujarat, a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Gujarat Legislative Assembly from 113—Thasra constituency has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Waghela Chhaganbhai Bhupatbhai to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ—LA/113/72 (27)]

आदेश

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1973

का० आ० 2327.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए गुजरात विधान-सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 110-शेहरा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सरदार सिंह भाईजी-भाई वारिया, पो० आ० पादेर्दी, तालुक शेहरा, जिला पंचमहल, गुजरात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ,

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचनाएं दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सरदार सिंह भाईजीभाई वारिया को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० गुज०-वि०स०/110/72 (28)]

ORDER

New Delhi, the 12th July, 1973

S.O. 2327.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sardarsinh Bhaijibhai Baria, At Post Paderdi, Taluka Shehra, District Panchmahals, Gujarat, a contesting candidate in the general election held in March, 1972, to the Gujarat Legislative Assembly from 110—Shehra constituency, has failed to lodge an account of his election expenses, as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sardarsinh Bhaijibhai Baria to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. GJ—LA/110/72 (28)]

आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1973

का० आ० 2328.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1971 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 91—कपिलामलाई निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पी० थ्यागाराजन, कल्लीपालायाम, पो० कोन्डालाम (वाया) नोयल, जिला सलेम (तमिलनाडु) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा भी अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ,

और, यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नहीं है ,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पी० थ्यागाराजन का संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० तमिलनाडु/वि०स०/91/71(66)]

ORDER

New Delhi, the 21st July, 1973

S.O. 2328.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri P. Thyagarajan, Kallipalayam, Kondalam Post, (Via) Noyyal, Salem Distt., (Tamil Nadu), a contesting candidate for the general election to the Tamil Nadu Legislative Assembly from 91—Kapilamalai constituency, held in March, 1971, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notices has not give any reason of explanation for the failure; and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri P. Thyagarajan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN/LA/91/71 (66)]

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1973

का. आ. 2329.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, तमिलनाडु सरकार के परामर्श से श्री टी. श्रीनिवासन के स्थान पर, श्री एच. के. गाजी, विशेष अपर सचिव, तमिलनाडु सरकार, लोक विभाग को तमिलनाडु राज्य के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में 25 जुलाई, 1973 के अपराह्न से अगले आदेशों तक एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है ।

[सं. 154/तमिलनाडु/73]

New Delhi, the 23rd July, 1973

S. O. 2329.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Tamil Nadu, hereby nominates Shri H. K. Ghazi, Special Additional Secretary to the Government of Tamil Nadu, Public Department, as the Chief Electoral Officer for the State of Tamil Nadu, with effect from the afternoon of 25th July, 1973 and until further orders vice Shri T. Srinivasan.

[No. 154/TN/73]

आदेश

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1973

का. आ. 2330.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 229-अमारेड्डी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पी. ईश्वरैय्या, मकान नं. 5-9-9/68, नौबत पहाड़, हैदराबाद-4 (आन्ध्र प्रदेश), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचनाएं दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पी. ईश्वरैय्या को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. आ. प्र.-वि स./229/72]

ORDER

New Delhi, the 26th July, 1973

S.O. 2330.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri P. Eshwaraiah, H. No. 5-9-9/68, Naobat Pahad, Hyderabad-4 (Andhra Pradesh), a contesting candidate for the general election held in March, 1972, to the Andhra Pradesh Legislative Assembly from 229-Kamareddy constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri P. Eshwaraiah to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/229/72]

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1973

का. आ. 2331.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए मैसूर विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 55-कुनिगल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोहम्मद गैबन खां, गंगोनाहाली, पो. आ. नागावाली, हेब्बूर होबली, तुमकूर तालुक, जिला तुमकूर (मैसूर), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचनाएं दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मोहम्मद गैबन खां को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. मैसूर-वि. स./55/72]

वी. नागसुब्रमण्यन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th July, 1973

S.O. 2331.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mohamed Gaiban Khan, Gangonahalli, Nagavalli Post, Hebbur Hobli, Tumkur Taluk, Tumkur District (Mysore), a contesting candidate for the general election to the Mysore Legislative Assembly held in March, 1972 from 55-Kunigal constituency, has failed to lodge an account of his election expenses, within the time and in the manner required by the Representation of the people Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mohamed Gaiban Khan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MY-LA/55/72]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 14 जून, 1973

आय-कर

का. आ. 2332.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री सरोजेन्द्र मोहन बनर्जी को, जो पश्चिमी बंगाल सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. अधिसूचना सं. 343 (फा. सं. 404/195/71-आई. टी. सी. सी.) तारीख 3 दिसम्बर, 1971 के अधीन की गई आशुतोष लहिरी की नियुक्ति तुरन्त रद्द की जाती है।

3. यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी।

[सं. 377 (फा. सं. 404/166/73-आई. टी. सी. सी.)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue & Insurance)

New Delhi, the 14th June, 1973

INCOME TAX

S.O. 2332.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby authorises Shri Sarojendra Mohan Banerjee, who is a Gazetted Officer of the West Bengal Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. The appointment of Shri Ashutosh Lahiri made in Notification No. 343 (F. No. 404/195/71-ITCC) dated the 3rd December, 1971 is cancelled with immediate effect.

3. This Notification shall come into force with immediate effect.

[No. 377 (F. No. 404/166/73-ITCC)]

नई दिल्ली, 15 जून, 1973

का. आ. 2333.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार,

1. श्री एस. वेनुगोपालन,
2. श्री ए. वी. तुम्बडे,
3. श्री आई. बी. भसीन,
4. श्री डी. पी. सुन्दरम,
5. श्री जी. एस. टुंग,
6. श्री आर. एन. बैजे,
7. श्री एस. थिरुगनंसमबंधन,
8. श्री एस. जी. कुदव,
9. श्री बी. एस. गोठे, और
10. श्री एम. एच. शेख,

नई दिल्ली, 15 जून, 1973

को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

2. अधिसूचना सं. 81 (फा. सं. 404/51/71-आई टी. सी. सी.), तारीख 15 मार्च, 1973 के अधीन श्री जी. के. दिवानी की और अधिसूचना सं. 161 (फा. सं. 404/232/72-आई. टी. सी. सी.) तारीख 21 अगस्त, 1962 के अधीन सर्वश्री डी. जे. एथले, वी. एम. नारगुडकर, वी. आई. यूसफ, जी. के. भावे, एन. के. लालवानी, डी. एस. प्रभु, आर. आर. पुरोहित और जी. ए. हेगडे की तथा अधिसूचना सं. 275 (फा. सं. 404/15/73 आई. टी. सी. सी.) तारीख 29 जनवरी, 1973 के अधीन श्री टी. जी. लालवानी की, नियुक्तियां तुरन्त रद्द की जाती हैं।

3. यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी।

[सं. 379 (फा. सं. 404/15/73-आई. टी. सी. सी.)]

New Delhi, the 15th June, 1973

S.O. 2333.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby authorises :

1. Shri S. Venugopalan,
2. Shri A. V. Tumbde,
3. Shri I. B. Bhasin,
4. Shri D. P. Sundaram,
5. Shri G. S. Tung,
6. Shri R. N. Vaze,
7. Shri S. Thirugnanasambandhan,
8. Shri S. G. Kudav,
9. Shri B. S. Gothe, and
10. Shri M. H. Shaikh

who are Gazetted Officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.

2. The appointments of Shri G. K. Devani under Notification No. 81 (F. No. 404/51/71-ITCC) dated 15th March, 1971 and S./Shri D. J. Athalye, V. M. Nargudkar, V. I. Yoosaf, G. K. Bhave, N. K. Lalwani, D. S. Prabhu, R. R. Purohit and G. A. Hedge under Notification No. 161 (F. No. 404/232/72-ITCC) dated 21st August, 1972 and Shri T. G. Lalwani under Notification No 275 (F. No. 404/15/73-ITCC) dated 29th January, 1973 are cancelled with immediate effect.

3. This Notification shall come into force with immediate effect.

[No. 379 (F. No. 404/15/73-ITCC)]

का. आ. 2334.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सर्वश्री बी. रवीबलन और टी. जौसेफ को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

2. अधिसूचना सं. 127 (फा. सं. 404/245/72-आई. टी. सी. सी.) तारीख 29 जून, 1972 के अधीन की गई श्री एम. पी. के. नायर की और अधिसूचना सं. 157 (फा. सं. 404/245/72-आई. टी. सी. सी.) तारीख 16 अगस्त, 1972 के अधीन की गई श्री पी सी. जौन की नियुक्ति 15 जून, 1973 से रद्द की जाती हैं।

3. यह अधिसूचना 15 जून, 1973 से प्रवृत्त होगी।

[सं. 381 (फा. सं. 404/176/73-आई. टी. सी. सी.)]

एम. एन. नाम्बियार, अवर सचिव

S.O. 2334.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby authorises S/Shri B. Ravibalan and T. Joseph Mathew who are Gazetted Officers of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.

2. The appointments of Shri M. P. K. Nair made under Notification No. 127 (F. No. 404/245/72-ITCC) dated 29th June, 1972 and Shri P. C. John under Notification No. 157 (F. No. 404/245/72-ITCC) dated 16th August, 1972 are cancelled with effect from 15th June, 1973.

3 This Notification shall come into force with effect from 15th June, 1973.

[No. 381 (F. No. 404/176/73-ITCC)]

M. N. NAMBIAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 जून 1973

का० आ० 2335.—*आयकर अधिनियम,* 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री देवी करुमारियम्मन थिरुकोइल मद्रास को, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए तमिल नाडु राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान होना अधिसूचित करती है।

[सं० 389 (फा० सं० 176/18/73 आई टी (ए आई)]

मदन किशोर पाण्डेय अवर सचिव

New Delhi, the 23rd June, 1973

S.O. 2335.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) (b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies Shri Devi Karumariamman Thirukkoil, Madras, to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purposes of the said section.

[No. 389 (F. No. 176/18/73-IT(AI)]

V. B. SRINIVASAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जून, 1973

का. आ. 2336.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संस्था को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली, विहित प्राधिकारी, द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।

संस्था

दि कर्नाटक इंस्टीट्यूट आफ अप्लाइड रिसर्च, समीरवाड़ी, जिला बीजापुर।

[सं. 397 (फा. सं. 203/41/72-आई. टी. ए. 2)]

टी. पी. झुनझुनवाला, उप-सचिव

New Delhi, the 30th June, 1973

S.O. 2336.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Agricultural Research, New Delhi the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (i) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 for a period of two years w.e.f. 1st April, 1973.

Institution

The Karnataka Institute of Applied Agricultural Research, Sameerwadi, Distt. Bijapur.

[No. 397 (F. No. 203/41/72-ITA II)]

T. P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1973

का आ 2337.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खंड 3 के उपखंड (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री एम० जी० बालासुब्रमणियन के स्थान पर श्री एम० दण्डपाणि, निदेशक, बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, को इंडियन बैंक का निदेशक नियुक्त करती है ।

[सं० फा० 9—2(4)—73-बी०ओ० 1(4)]

(Department of Banking)

New Delhi, the 6th July, 1973

S.O. 2337.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the National Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri M. Dandapani, Director, Department of Banking, Ministry of Finance, New Delhi as a Director of Indian Bank, *vice* Shri M. G. Balasubramanian.

[No. F. 9-2 (4)/73-BO. I (4)]

का.आ. 2338.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खंड 3 के उपखंड (ज) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री वी०एम० भिड़े के स्थान पर श्री एम० जी० बालासुब्रमणियन, अवर सचिव, बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, को सेंट्रल बैंक आफ इंडिया का निदेशक नियुक्त करती है ।

[सं० फा० 9—2(4)—73-बी०ओ० 1(2)]

S.O. 2338.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri M. G. Balasubramanian, Additional Secretary, Department of Banking, Ministry of Finance, New Delhi as a Director of Central Bank of India, *vice* Shri V. M. Bhide.

[No. F. 9-2 (4)/73-BO. I (2)]

का आ. 2339.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खंड 3 के उपखंड (ज) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री एम० जी० बालासुब्रमणियन के स्थान पर श्री के० पी० गीताकृष्णन, निदेशक बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, को इंडियन ओवरसीज बैंक का निदेशक नियुक्त करती है ।

[सं० फा० 9-2(4) 73 बी. ओ I(3)]

सी० डब्ल्यू मीरचंदानी, अवर सचिव

S.O. 2339.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri K. P. Geethakrishnan, Director, Department of Banking, Ministry of Finance, New Delhi as a Director of Indian Overseas Bank, *vice* Shri M. G. Balsubramanian.

[No. F. 9-2 (4)/73-BO. I (3)]

C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1973

का. आ. 2340.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री आर. ए. गुलमुहम्मद को 10 जुलाई, 1973 से प्रारंभ होने वाली और 9 जुलाई, 1974 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए देना बैंक का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करती है ।

[सं. एफ. 9-4/(11)/73-बी. ओ.-1-1]

New Delhi, the 9th July, 1973

S.O. 2340.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby reappoints Shri R. A. Gulmohamed as the Managing Director of Dena Bank for the period commencing on 10th July, 1973 and ending with 9th July, 1974.

[No. F. 9-4/11/73-BO. I-1]

का. आ. 2341.—राष्ट्रीयकृत बैंक प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड 7 के साथ पठित खंड 5 के उपखंड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री आर. ए. गुलमुहम्मद को, जो 10 जुलाई, 1973 से देना बैंक के प्रबन्ध निदेशक पुनः नियुक्त किए गए हैं, उसी तारीख से देना बैंक के निदेशक-बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है ।

[सं. एफ-9-4/11/73-बी ओ-1-2]

डी. एम. सुकथनकर, निदेशक

S.O. 2341.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 3, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri R. A. Gulmohamed, who has been re-appointed as Managing Director of Dena Bank with effect from 10th July, 1973, to be the Chairman of the Board of Directors of Dena Bank with effect from the same date.

[No. F. 9-4/11/73-BO. I-2]

D. M. SUKTHANKAR, Director.

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1973

का. आ. 2342.—राष्ट्रीयकृत बैंक प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड 8 के उपखंड (1) के साथ पठित खंड 3 के उपखंड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री बी. के मुकर्जी को 18 जुलाई, 1973 से प्रारंभ होने वाली और 31 अगस्त, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इलाहाबाद बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त करती है ।

[सं. फा. 9-4/11/73-बी. ओ. 1-1]

New Delhi, the 16th July, 1973

S.O. 2342.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby reappoints Shri B. K. Mookerjea as the Managing Director of Allahabad Bank for the period commencing on 18th July, 1973 and ending with 31st August, 1973.

[No. F. 9-4/11/73-BO. I-1]

का. आ. 2343.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 के उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री बी. के. मुकर्जी को, जो 18 जुलाई, 1973 से इलाहाबाद बैंक के प्रबन्ध निदेशक पुनः नियुक्त किए गए हैं, उसी तारीख से इलाहाबाद बैंक के निदेशक-बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है ।

[सं. एफ-9-4/11/73-बी. ओ. 1-2]

डी. एन. घोष, संयुक्त सचिव

S.O. 2343.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri B. K. Mookerjea who has been re-appointed as Managing Director of Allahabad Bank with effect from 18th July, 1973, to be the Chairman of the Board of Directors of Allahabad Bank with effect from the same date.

[No. F. 9-4/11/73-BO. I-2]

D. N. GHOSH, Joint Secy.

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1973

का. आ. 2344.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री बी. के दत्त के स्थान पर श्री एम. सेन सर्मा को पहली अगस्त, 1973 से प्रारंभ होने वाली और 31 जुलाई, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं. फा. 9-4/11/73-बी. ओ. 1-1]

New Delhi, the 19th July, 1973

S.O. 2344.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri M. Sen Sarma as the Managing Director of United Bank of India for the period commencing on 1st August, 1973 and ending with 31st July, 1976, vice Shri B. K. Dutt.

[No. F. 9-4/11/73-BO. I-1]

का. आ. 2345.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 के उपखंड (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् श्री. एम. सेन सर्मा को, जिसे पहली अगस्त, 1973 से यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के निदेशक-बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है ।

[सं. फा. 9-4/11/73-बी. ओ 1-2]

एन. सी. सेन गुप्ता, सचिव

S. O. 2345.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri M. Sen Sarma, who has been appointed as Managing Director of United Bank of India with effect from 1st August, 1973, to be the Chairman of the Board of Directors of United Bank of India with effect from the same date.

[No. F. 9-4/11/73-BO I-2]

N. C. SEN GUPTA, Secy.

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1973

का. आ. 2346.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध दी साहूकार बैंक लिमिटेड, लुधियाना पर उनके बंगा, जिला जालन्धर, पंजाब स्थित भूखण्ड के विषय में 15 मार्च, 1974 तक लागू नहीं होंगे ।

[सं. 15(23)-बी. ओ. 3/73]

New Delhi, the 31st July, 1973

S.O. 2346.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply to the Sahukara Bank Ltd., Ludhiana, in respect of the plot of land held by it at Banga, Jullundur District, Punjab, till the 15th March, 1974

[No. 15(23)-B.O. III/73]

का. आ. 2347.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध दी कैथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड, त्रिचूर पर बैंक की ग्राम पालाकुझा, तालुका मुवात्तुपुझा, जिला एर्नाकुलम्, केरल राज्य स्थित 2.59 एकड़ की अचल सम्पत्ति के विषय में 5 अप्रैल, 1974 तक लागू नहीं होंगे ।

[सं. 15(25)-बी. ओ. 3/73]

S.O. 2347.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply, till the 5th April, 1974, to the Catholic Syrian Bank Ltd., Trichur, in respect of the immovable property measuring 2.59 acres held by it at Palakuzha Village, Muvattupuzha Taluk, Ernakulam District, Kerala State.

[No. 15(25)-B.O. III/73]

का. आ. 2348.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता पर 21 जुलाई, 1973 से दो वर्ष तक की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे, जहां तक उनका संबंध दी बंगाल एनेमिल वर्कर्स लिमिटेड, कलकत्ता के 6.56 लाख रुपये के चुकता मूल्य के शेयरों में बैंक की सम्पत्ति से है ।

[सं. 15(21)-बी. ओ. 3/73]

हृषीकेश गुहा, अवर सचिव

S.O. 2348.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act will not apply to the United Bank of India, Calcutta, for a period of two years from the 21st July, 1973, in so far as they relate to its holdings in the shares of the paid up value of Rs. 6.56 lakhs of the Bengal Enamel Works Ltd., Calcutta.

[No. 15(21)-B.O. III/73]

H. K. GUHA, Under Secy.

नयी दिल्ली, 1 अगस्त, 1973

का० आ० 2349—कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 (1963 का 10वा) की धारा 10 के खंड (ग) के द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री के० एन० चन्ना, अवर सचिव, कृषि मंत्रालय, सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग को श्री एम० ए० कुरेशी के स्थान पर कृषिक पुनर्वित्त निगम का निदेशक नामित करती है ।

[सं०एफ० 14/9/71-कृषि-ऋण एक]

अमल कुमार दत्त, संयुक्त सचिव,

New Delhi, the 4th August, 1973

S.O. 2349.—In exercise of the powers conferred upon it by clause (c) of Section 10 of the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963 (10 of 1963), the Central Government hereby nominates Shri K. N. Channa, Additional Secretary, Ministry of Agriculture, Department of Community Development and Co-operation, as a Director of the Agricultural Refinance Corporation *vice* Shri M. A. Quraishi.

[No. F. 14/9/71-ACI]

A. K. DUTT, Joint Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1973

का० आ० 2350.—यत केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अकार्बनिक वर्णकों से संबंधित अधिसूचना सं० का० आ० 2673, तारीख 1 सितम्बर, 1966 में, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए नीचे विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करना आवश्यक और समीचीन है,

और यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त निर्मित प्रस्तावों को निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम, 2 के उपनियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेजा है,

अत: अब, उक्त उप-नियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को, उससे सम्भाव्यत: प्रभावित होने वाली जनता की जानकारी के लिए, प्रकाशित करती है।

2 यह सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजना चाहे, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् "वर्ल्ड ट्रेड सेंटर" 14/1 बी, इजरा स्ट्रीट (सातवीं मंजिल), कलकत्ता-1 को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2673, तारीख 1 सितम्बर, 1966 में,—

(i) उपाबंध-I में, क्रम सं० 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात –

"4 नील
5 लोहे का काला ऑक्साइड
6 विनिर्मित लाल ऑक्साइड
7 प्राकृतिक लाल ऑक्साइड
8 गैरिक (गैरु और रामरज)
9 प्राकृतिक सिएना (कच्ची और पकाई गई)
10 प्राकृतिक अम्बर (कच्चा और पकाया गया)"

(ii) उपाबंध II- के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात –

"उपाबन्ध-II

1. जस्ता ऑक्साइड	भा० मा०	35–1950
	या	
	भा० मा०	1399–1965
	या	
	भा० मा०	1880–1967
2 रक्त-सिंदूर	भा० मा०	57–1965
3 सफेदा	भा० मा०	31–1950
4 नील	भा० मा०	55–1950
5. काला ऑक्साइड	भा० मा०	44–1969
6 विनिर्मित लाल ऑक्साइड	भा० मा०	44–1969
7. प्राकृतिक लाल ऑक्साइड	भा० मा०	44–1969
	या	
	भा० मा०	1684–1960
8 गैरिक (गैरु और रामरज)	भा० मा०	44–1969
9 प्राकृतिक सिएना (कच्ची और पकाई गई)	भा० मा०	41–1969
10 प्राकृतिक अम्बर (कच्चा और पकाया गया)	भा० मा०	44–1969

[सं० 6(40)/72 नि० नि० सभा नि० सं०]

Ministry of Commerce

ORDER

New Delhi, the 11th August, 1973.

S. O. 2350.—Whereasthe Central Government is of opinion that,in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient to amend the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce, No. S. O. 2673, dated the 1st September, 1966, regarding inorganic pigments, in the manner specified below, for the development of the export trade of India;

And whereas the Central Government has forwarded the proposals in that behalf to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (quality Control and Inspection) Rules, 1964 ;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same, within thirty days from the date of publication of this order in the official Gazette, to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1B, Ezra Street (7th Floor), Calcutta-1.

Proposals

In the Notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce, No. S. O. 2673, dated the 1st September, 1966, —

(i) in Annexure-I, after serial No. 3 and the entries relating thereto the following shall be inserted, namely :—

"4. Ultramarine blue
5. Blackr Oxide of iron
6. Manufactured red oxide
7. Natural red oxide
8. Ochre (red and yellow)
9. Natural Sienna (raw and burnt)
10. Natural umber (raw and burnt),

(ii) for Annexure-II, the following Annexure shall be substituted, namely :—

"ANNEXURE-II

1. Zinc oxide	IS: 35—1950 or IS: 3399—1965 or IS: 1880—1967
2. Red lead	IS: 57—1965
3. White lead	IS: 34—1950
4. Ultramarine blue . . .	IS: 55—1950
5. Black Oxide	IS: 44—1969
6. Manufactured red oxide . . .	IS: 44—1969
7. Natural red oxide . .	IS: 44—1969 or IS: 1684—1960
8. Ochre (red and yellow) . .	IS: 44—1969
9. Natural sienna (raw and burnt) .	IS: 44—1969
10. Natural umber (raw and burnt) .	IS: 44—1969".

[No. 6(40)/72-EI&EP]

आदेश

का० आ० 2351:—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3978, तारीख 20 दिसम्बर, 1965 में, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए नीचे विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करना आवश्यक और समीचीन है ;

और यत केन्द्रीय सरकार ने उस निमित्त प्रस्ताव को निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के 11 नियम के उपनियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेजा है :

अतः अब, उक्त उपनियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्ताव को उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाली जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है

2 यह सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति, जो उक्त प्रस्ताव के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजना चाहे, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् "वर्ल्ड ट्रेड सेंटर", 14/1 बी, हजरा स्ट्रीट, (सातवीं मंजिल), कलकत्ता–1 को भेज सकेगा ।

प्रस्ताव

भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3978 तारीख 20 दिसम्बर, 1965 की अनुसूची में "8 लाल आक्साइड 19. रामरज ।" क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां लुप्त कर दी जाएंगी और परिणामस्वरूप क्रम संख्याएं 10 और 11 क्रमशः क्रम संख्याएं 8 और 9 के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएगी ।

[सं० 6(40)/72 नि०नि०और नि०सं०]

ORDER

S.O. 2351.—Whereas the Central Government is of opinion that, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient to amend the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce, No. S.O. 3978, dated the 20th December, 1965, in the manner specified below, for the development of the export trade of India ;

And whereas the Central Government has forwarded the proposal in that behalf to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 ;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposal for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposal may forward the same, within thirty days from the date of publication of this Order in the Official Gazette, to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-1.

Proposal

In the Schedule to the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce, No. S.O. 3978, dated the 20th December, 1965, Serial Numbers and entries "8. Red oxide. 9. Yellow ochre" shall be omitted, and consequently Serial Numbers 10 and 11 shall be re-numbered as Serial Numbers 8 and 9 respectively.

[No. 6(40)/72-EI&EP]

का०आ० 2352.—यत: निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2675, तारीख 1 सितम्बर, 1966 मे नीचे विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने की प्रस्थापना करती है और उस निमित्त प्रस्ताव को निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम II के उपनियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेजा है ;

अत, अब, उक्त उपनियम के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्ताव को, उससे संभाव्यत: प्रभावित होने वाली जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है ।

2 यह सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति, जो उक्त प्रस्ताव के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजना चाहे, इस अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् "वर्ल्ड ट्रेड सेंटर" 14/1बी, हजरा स्ट्रीट (सातवी मजिल) कलकत्ता–1 को भेज सकेगा ।

प्रस्ताव

भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2675 तारीख 1 सितम्बर, 1966 के स्पष्टीकरण में, और (ग) सफेदा" शब्दों, कोष्टको और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

"(ग) सफेदा, (घ) नील (ङ) लोहे का काला आक्साइड, (च) विनिर्मित लाल आक्साइड, (छ) प्राकृतिक लाल आक्साइड, (ज) गैरिक (गैरू और रामरज), (झ) प्राकृतिक सिएना (कच्ची और पकाई गई), (ञ) प्राकृतिक अम्बर (कच्चा और पकाया गया)" ।

[सं० 6(40)/72 नि० नि० और नि० सं०]

S.O. 2352.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by section 8 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) proposes to amend the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce, No. S.O. 2675, dated the 1st September, 1966, in the manner specified below, and has forwarded the proposal in that behalf to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 ;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposal for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said

proposal may forward the same, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-1.

Proposal

In the **Explanation** to the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S. O. 2675, dated the 1st September, 1966, for the words, brackets and letter "and (c) White lead", the following shall be substituted, namely :—

"(c) White lead, (d) Ultramarine blue, (e) Black oxide of iron, (f) Manufactured red oxide, (g) Natural red oxide, (h) Ochre (red and yellow), (i) Natural sienna (raw and burnt) and (j) Natural umber (raw and burnt)".

[No. 6(40)/72-FI&EP]

आदेश

का० आ० 2353.—यतः निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) द्वारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि पिसी हुई लाल मिर्च निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगी;

और यतः उक्त प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार ने नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हे निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है;

अतः, अब, उक्त उप-नियम के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को एतद्द्वारा सभाव्यतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है ।

2. यह सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहे तो वह उन्हे इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, "वर्ल्ड ट्रेड सेंटर" 14/1बी, इजरा स्ट्रीट (सातवीं मंजिल), कलकत्ता-1 को भेज सकता है ।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि पिसी हुई लाल मिर्च निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगी;

(2) इस आदेश के उपाबन्ध में दिए गए, पिसी हुई लाल मिर्च का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1973 के प्रारूप के अनुसार निरीक्षण के प्रकार की निरीक्षण के उस प्रकार के रूप मे विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व पिसी हुई लाल मिर्च को लागू किया जाएगा ।

(3) पिसी हुई लाल मिर्च श्रेणीकरण और चिह्नन नियम, 1964 के अधीन बनाये गए श्रेणी अभिधानों को पिसी हुई लाल मिर्च के लिए मानक विनिर्देशों के रूप मे मान्यता देना;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान पिसी हुई लाल मिर्च के निर्यात का तब तक प्रतिषेध करना जब तक ऐसी पिसी हुई लाल मिर्च के पैकेजों और आधानों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त चिन्ह या सील या लेबल चिपकाया या लगाया न गया हो ।

3. इस आदेश की कोई भी बात, भावी क्रेताओं को 20 रु० मूल्य से अनधिक के पिसी लाल मिर्च के नमूनों के स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी ।

4. इस आदेश में पिसी हुई लाल मिर्च से लाल मिर्च के पौधे (जीनस कैपसिकम) के शुद्ध, साफ, सुखाए हुए, पके फलों को पीसने से अभिप्राप्त उत्पाद अभिप्रेत है ।

उपाबन्ध

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अन्तर्गत बनाए जाने के लिए प्रस्थापित प्रारूप—नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम पिसी हुई लाल मिर्च का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1973 है ।

(2) ये को प्रवृत होंगे ।

2. परिभाषा.—इन नियमों में 'पिसी हुई लाल मिर्च' से लाल मिर्च के पौधे (जीनस कैपसिकम) के शुद्ध, साफ, सुखाये हुए, पक्के फलों को पीसने से अभिप्राप्त उत्पाद अभिप्रेत है ।

3. निर्यात से पूर्व पिसी हुई लाल मिर्च के निरीक्षण की प्रक्रिया.—कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1), साधारण श्रेणीकरण और चिह्नन नियम, 1937 और पिसी हुई लाल मिर्च श्रेणीकरण और चिह्नन नियम, 1964 के उपबन्ध, निर्यात से पूर्व पिसी हुई लाल मिर्च के निरीक्षण को, यावत्शक्य लागू होंगे ।

[सं० 6(22)/72-नि०नि० और नि०सं०]

ORDER

S.O. 2353.—Whereas, the Central Government is of opinion that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality, Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, that chilli powder should be subjected to quality, control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within thirty days of the date of publication of this Order in the Official Gazette, to the Export Inspection Council, "World Trade Centre", 14/1B Ezra Street (7th floor), Calcutta-1.

Proposals

(1) To notify that chilli powder shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To specify the type of inspection in accordance with the Draft Export of Chilli Powder (Inspection) Rules, 1973, set out in the Annexure to this order as the type of inspection which shall be applied to such chilli powder prior to export;

(3) To recognise the grade designations formulated under the Chilli Powder Grading and Marking Rules, 1964, as the standard specifications for chilli powder;

(4) To prohibit the export in the course of international trade of chilli powder, unless a mark or seal or label recognised by the Central Government has been affixed or applied to packages or containers of such chilli powder;

3. Nothing in this order shall apply to export by sea, land or air of samples of chilli powder not exceeding in value of rupees twenty to prospective buyers.

4. In this order, "chilli powder" means the product obtained by grinding pure, clean, dried, ripe fruits of the genus **Capsicum.**

ANNEXURE

Draft Rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality, Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Export of Chilli Powder (Inspection) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the.....

2. **Definition.**—In these rules "Chilli Powder" means the product obtained by grinding pure, clean, dried, ripe fruits of the genus **Capsicum.**

3. **Procedure of inspection of chilli powder prior to export.**—The provisions of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), the General Grading and Marking Rules, 1937 and the Chilli Powder Grading and Marking Rules, 1964, shall so far as may be, apply to the inspection of chilli powder prior to export.

[No. 6 (22)/72-EI&EP]

का०आ० 2354.—यतः केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पिसी हुई लाल मिर्च श्रेणीकरण और चिह्नन नियम, 1964 के नियम 5 में वर्णित श्रेणी अभिधानों की पिसी हुई लाल मिर्च के सम्बन्ध में यह घोषित करने के प्रयोजन के लिये मान्य करने की प्रस्थापना करती है कि जहां पिसी हुई लाल मिर्च से भरे हुए पैकजों या आधानों पर ऐसे चिह्नन लगाये गये है, वहां यह मान लिया जायेगा कि ऐसे पैकजों या आधानों में भरी पिसी हुई लाल मिर्च उक्त अधिनियम की धारा 6 के खंड (ग) के अधीन उन्हें लागू मानक विनिदेशों के अनुरूप है;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त प्रस्ताव बनाया है और उसे निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है;

अतः, अब, उक्त उप-नियम के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रस्तावों को एतद्द्वारा सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित करती है ।

2 यह सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्ताव के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजना चाहे तो वह उन्हें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, 'वर्ल्ड ट्रेड सन्टर', 14/1बी०, इजरा स्ट्रीट (सातवीं मंजिल), कलकत्ता-1 को भेज सकता है ।

परिभाषा :—इस अधिसूचना में पिसी हुई लाल मिर्च से लाल मिर्च के पौधे (जीनस कैपसिकम) के शुद्ध, साफ, सुखाये हुए पक्क फलों को पीसने से अभिप्राप्त उत्पाद अभिप्रेत है ।

[सं० 6(22)/72-नि०नि०और नि०सं०]

S.O. 2354.—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 8 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), proposes to recognise the grade designation mark described in rule 5 of the Chilli Powder Grading and Marking Rules, 1964, in relation to chilli powder, for the purpose of denoting that where a package or container containing chilli powder is affixed with such mark, the chilli powder in such package or container shall be deemed to be in conformity with the standard specifications applicable thereto under clause (c) of section 6 of the said Act;

And whereas the Central Government has formulated the aforesaid proposal and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality, Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposal for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposal may forward the same within thirty days of the date of publication of this Notification in the Official Gazette, to the Export Inspection Council, "World Trade Centre", 14/1-B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-1.

Explanation.—In this notification, "chilli powder" means the product obtained by grinding pure, clean, dried ripe fruits of the genus **Capsicum.**

[No. 6(22)/72-EI&EP]

आदेश

का०आ० 2355.—यतः (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिये ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि अलौह चद्दरें छड़ें तथा ट्यूबें निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण के अधीन होनी चाहियें;

और यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिये नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाये हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है,

अतः, अब, उक्त उप-नियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाली जनता की जानकारी के लिये प्रकाशित करती है ।

2 यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजने की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, 'वर्ल्ड ट्रेड सैन्टर' 14/1बी०, एजरा स्ट्रीट (नवीं मंजिल), कलकत्ता-1 को भेज सकेगा ।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि अलौह चद्दरें, छड़ें तथा ट्यूबें निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण के अधीन होंगी,

(2) इस आदेश के उपाबन्ध में दिये गये अलौह चद्दरें, छड़ों तथा ट्यूबों का निर्यात (निरीक्षण) प्रारूप नियम, 1973 के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को निरीक्षण के उस प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो ऐसी अलौह चद्दरों, छड़ों तथा ट्यूबों पर लागू किया जायेगा ।

(3) भारतीय या अन्य राष्ट्रीय मानकों को अलौह चद्दरों, छड़ों तथा ट्यूबों के लिये मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना ।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसी अलौह चद्दरों, छड़ों तथा ट्यूबों के निर्यात का तब तक प्रतिषेध करना जब तक कि उनके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किसी एक द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि अलौह चद्दरें, छड़ें तथा ट्यूबें निर्यात के योग्य है ।

3. इस आदेश की कोई भी बात अलौह चद्दरों, छड़ों या ट्यूबों के नमूनों के भावी कताओं के लिये निर्यात पर लागू नहीं होगी जिनका पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य एक सौ पच्चीस रुपये से अधिक नहीं है ।

4. **परिभाषा**—इस आदेश में अलौह चद्दरों, छड़ों तथा ट्यूबों से एल्यूमीनियम या तांबे और उनके मिश्र धातुओं की प्लेटें, चद्दरें, घेरे, पट्टियां, छड़ें, दण्ड, चपटे टुकड़े, तार तथा ट्यूबें अभिप्रेत होंगी, किन्तु इनके अन्तर्गत अधिसूचना सं० का०आ० 3492, ता० 27 दिसम्बर 1969 में निर्दिष्ट विद्युत् केबिल तथा चालक सम्मिलित नहीं होंगे ।

उपबंध

(निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 के अधीन बनाऐ गऐ प्रारूप नियम)

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1) इन नियमों का नाम अलौह चद्दरों, छड़ों तथा ट्यूबों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1973 है ।

2 (2) ये को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषायें**.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 अभिप्रेत है ।

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन कोचीन, मद्रास, कलकत्ता मुम्बई और दिल्ली में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई एक अभिप्रत है ।

(ग) "अलौह चद्दरों, छड़ों तथा ट्यूबों" से एलूमीनियम या तांबे और उनके मिश्र धातुओं की प्लेट, चद्दरें, घरे पट्टियां, छड़ें, दण्ड, चपट टुकड़े तथा तार ट्यूब अभिप्रेत होंगी किन्तु इनके अन्तर्गत अधिसूचना सं० का०आ० 3492, ता० 27 सितम्बर, 1968 में निर्विष्ट विद्युत् 'केबिल तथा चालक' सम्मिलित नही होंगे ।

3. **निरीक्षण का आधार**.—अलौह चद्दरों, छड़ों तथा ट्यूबों का निरीक्षण यह देखने की दृष्टि से किया जायगा कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों (जिन्हें इसके पश्चात् मानक विनिदश कहा गया है) के अनुरूप हैं ।

4. **निरीक्षण की प्रक्रिया**—(1) अलौह चद्दरों, छड़ों तथा ट्यूबों के निर्यात करने का आशय रखने वाले कोई निर्यात कर्त्ता ऐसा करने के लिये अपने आशय की लिखित सूचना देगा तथा ऐसी सूचना के साथ निर्यात-संविदा में अनुबन्ध विनिर्देशों की घोषणा तकनीकी विशषताय बताते हुए निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किसी एक को देगा ताकि वह नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके । उक्त निर्यातकर्त्ता या विनिर्माता निरीक्षण के लिये ऐसी सूचना की एक प्रति निर्यात निरीक्षण परिषद् के कार्यालय या तो 14/1-बी०, इजरा स्ट्रीट (7वी मंजिल), कलकत्ता-1 या अमन चैम्बर्स, 113 महर्षि कर्वे रोड, मुम्बई-4 या मनोहर बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-11, या 13/37, उत्तरी विस्तार क्षेत्र, आर्य समाज रोड, नई दिल्ली-5 में पृष्ठांकित करेगा ।

(2) निर्यातकर्त्ता या विनिर्माता परेषण पर दिये गये पहचान के पोत परिवहन चिह्न भी अभिकरण को देगा ।

(3) उप-नियम(1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा पोत-लदान की अनुसूचित तारीख से कम से कम 10 दिन पहले अभिकरण तथा परिषद् के कार्यालय में पहुंच जायेंगी ।

(4) उप-नियम(1) तथा (2) के अधीन सूचना, घोषणा तथा पहचान का पोत-परिवहन चिह्न प्राप्त होने पर अभिकरण नियम 3 तथा परिषद् द्वारा इस सम्बन्ध में अनुदेशो, यदि कोई हो, के अनुसार अलौह चद्दरों, छड़ों या ट्यूबों का निरीक्षण करेगा ।

(5) निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात्, अभिकरण परेषण के पैकजों को तुरन्त इस प्रकार सील करेगा कि सील किये हुए माल के के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सके । अस्वीकृत होने की दशा में यदि निर्यातकर्त्ता की ऐसी वांछा हो, तो अभिकरण द्वारा परेषण सील नही किया जा सकेगा । किन्तु ऐसे मामलों में, निर्यातकर्त्ता को अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील करने का हक नही होगा ।

(6) जब अभिकरण का समाधान हो जाये कि अलौह चद्दरों, छड़ों या ट्यूबों का परेषण नियम 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, तो वह निरीक्षण की समाप्ति के सात दिन के भीतर निर्यातकर्त्ता को यह घोषणा करते हुए एक प्रमाणपत्र देगा कि परेषण निर्यात योग्य है परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता वहा वह उक्त सात दिनों की अवधि के अन्दर ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इन्कार कर देगा तथा ऐसी इंकारी की सूचना के उसके कारणों सहित निर्यातकर्त्ता को दे देगा ।

(7) जैसे ही और जब अभिकरण द्वारा अपेक्षित हो, निर्यातकर्त्ता अलौह चद्दरों, छड़ों तथा ट्यूबों के नमूने मुफ्त अपने कारखाने गोदाम (गोदामों) से प्रदाय करेगा किन्तु नमूने आवश्यक निरीक्षण तथा परख के पश्चात् अभिकरण द्वारा लौटा दिये जायेंगे ।

5. **निरीक्षण का स्थान**.—इन नियमों के प्रयोजन के लिये अलौह चद्दरों, छड़ों या ट्यूबों का निरीक्षण

(क) विनिर्माता के परिसर में या

(ख) उस परिसर में जहां अलौह चद्दरें, छड़ें या ट्यूबें या निर्यातकर्त्ता द्वारा प्रस्थापित की जाती है, परन्तु वहां पर्याप्त सुविधायें हों, किया जायेगा ।

6. **निरीक्षण शुल्क**.—इन नियमों के अधीन पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक सौ रुपये के लिये पचहत्तर पैसे की दर से, निम्नतम एक सौ रुपये तक के अधीन रहते हुए निरीक्षण फीस के रूप में फीस दी जायगी ।

7. अपील(1) नियम 4 के उप-नियम(5) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन, नियम 4 के उप-नियम (6) के अधीन अभिकरण की प्रमाणपत्र जारी करने से इंकारी द्वारा व्यथित व्यक्ति उसके द्वारा ऐसी इंकारी की संसूचना की प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके प्रयोजन के लिये नियुक्त विशेषज्ञ के एक पैनल को, जिसमें तीन से अन्यून व्यक्ति होंगे, अपील कर सकेगा ।

(2) विशेषज्ञों के पैनल का अधिवेशन करने के लिये गणपूर्ति उक्त पैनल के तीन विशेषज्ञों की होगी ।

(3) ऐसी अपील पर उक्त पैनल का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

[सं० 6(30)/72-नि०नि० तथा नि०सं०]

एम०के०वी० भटनागर, अवर सचिव

ORDER

S.O. 2355.—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), Non-ferrous Sheets, Rods and Tubes should be subject to quality control and inspection prior to export.

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same, within thirty days of the date of publication of this Order in the Official Gazette, to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1-B, Ezra Street, 7th Floor, Calcutta-1.

PROPOSALS

(1) To notify that the non-ferrous sheets, rods and tubes shall be subject to quality control and inspection prior to export.

(2) To specify the type of inspection in accordance with the draft Export of Non-ferrous Sheets, Rods and Tubes (Inspection) Rules, 1973, set out in the Annexure to this Order, as the type of inspection which will be applied to such non-ferrous sheets, rods and tubes.

(3) To recognise the Indian or other national standards as standard specifications for non-ferrous sheets, rods and tubes.

(4) To prohibit the export, in the course of international trade, of such non-ferrous sheets, rods and tubes, unless the same are accompanied by a certificate issued by any of the Export Inspection Agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the non-ferrous sheets, rods or tubes are export-worthy.

3. Nothing in this Order shall apply to the export of samples on non-ferrous sheets, rods or tubes to prospective buyers, the f.o.b. value of which does not exceed rupees one hundred and twenty-five.

4. **Definition.**—In this Order "non-ferrous sheets, rods and tubes" shall mean plates, sheets, circles, strips, rods, bars, flats, wires and tubes of aluminium or copper and their alloys, but shall not include "electric cables and conductors" referred to in the Notification No. S.O. 3492 dated the 27th September, 1968.

ANNEXURE

[Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1973].

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Export of Non-ferrous Sheets, Rods and Tubes (Inspection) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the.....

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Agency" means any one of the Export Inspection Agencies established by the Central Government at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay and Delhi under section 7 of the Act;

(c) "non-ferrous sheets, rods and tubes" shall mean plates, sheets, circles, strips, rods, bars, flats, wires and tubes of aluminium or copper and their alloys, but shall not include "electric cables and conductors" referred to in the Notification No. S.O. 3492, dated the 27th September, 1968.

3. **Basis of inspection.**—Inspection of non-ferrous sheets, rods or tubes shall be carried out with a view to seeing that the same conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act (hereinafter referred to as the standard specification).

4. **Procedure of inspecton.**—(1) Any exporter or manufacturer intending to export non-ferrous sheets, rods or tubes shall give intimation in writing of his intention so to do and submit along with such intimation a declaration of the specifications stipulated in the export-contract giving technical characteristics to any of the Export Inspection Agencies to enable it to carry out inspection in accordance with rule 3. The said exporter or manufacturer shall at the same time endorse a copy of such intimation for inspection to the office of the Export Inspection Council either at 14/1-B, Ezra Street, 7th floor, Calcutta-1, or at Aman Chambers, 113, Maharshi Karve Road, Bombay-4 or at Manohar Buildings, Mahatma Gandhi Road, Eranakulam, Cochin-11, or at 13/37, Western Extension Area, Arya Samaj Road, New Delhi-5.

(2) The exporter or manufacturer shall also furnish to the agency the shipping marks of identification applied on the consignment.

(3) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall reach the offices of the Agency and the Council not less than ten days prior to the scheduled date of shipment.

(4) On receipt of the intimation, declaration and shipping marks of identification under sub-rules (1) and (2), the Agency shall carry out the inspection of non-ferrous sheets, rods or tubes in accordance with rule 3 and the instructions, if any, issued by the Council in this regard.

(5) After completion of inspection, the Agency shall immediately seal the packages in the consignment in a manner as to ensure that the sealed goods cannot be tampered with. In case of rejection, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the Agency. In such cases, however, the exporter shall not be entitled to perfer any appeal against the rejection.

(6) When the Agency is satisfied that the consignment of non-ferrous sheets, rods or tubes complies with the requirements of rule 3, it shall within 7 days of completion of inspection, issue a certificate to the exporter declaring that the consignment is export-worthy:

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall within the said period of 7 days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

(7) As and when required by the Agency, the exporter shall supply free of charge samples of non-ferrous sheets, rods or tubes from his factory|gowodn(s). The samples shall, however, be returned by the Agency after necessary inspection and testing.

5. **Place of inspection.**—Inspection of non-ferrous sheets, rods or tubes for the purpose of these rules shall be carried out :—

(a) at the premises of the manufacturer, or

(b) at the premises at which the non-ferrous sheets, rods or tubes are offered by the exporter, provided adequate facilities for the purpose exist therein.

6. **Inspection fee.**—A fee at the rate of seventy five paise for every hundred rupees of f.o.b. value subject to a minimum of rupees one hundred shall be paid as inspection fee under these rules.

7. **Appeal.**—(1) Subject to the provisions contained in sub-rule (5) of rule 4 any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (6) of rule 4 may

within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The quorum to constitute a meeting of the panel of experts shall be of three experts of the said panel.

(3) The decision of the said panel on such appeal shall be final.

[No. 6(30)/72-PJ&EP]

M. K. B. BHATNAGAR, Under Secy.

(आन्तरिक व्यापार विभाग)

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1973

का. आ. 2356.—संप्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची में, मद 17 के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"18 — रामकृष्ण मठ और मिशन का नाम और संप्रतीक, जिसमें जल में तैरता हुआ हंस, अग्रभाग में कमल और पृष्ठ-भूमि में उदीयमान सूर्य होगा, ये सभी एक जंगली सर्प द्वारा घिरे हुए होंगे और निचले भाग में 'तन्नोहंसः प्रचोदयात्' शब्द अंकित होंगे ।

[फा. सं. 23(35) आ. या./72]

(Department of Internal Trade)

New Delhi, the 4th August, 1973

S.O. 2356.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950, the Central Government hereby directs that in the Schedule to the said Act, after item 17, the following item shall be added namely :—

"18. The name & emblem of the Rama Krishna Math and Mission consisting of a Swan floating on waters, with a Lotus in the foreground and the rising sun in the background, the whole being encircled by a wild serpent, with the words 'तन्नोहंसः प्रचोदयात्' superimposed on the bottom portion."

[F. No. 23(35)-IT/72]

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1973

का०आ० 2357.—केन्द्रीय सरकार, आगरा मर्चेंटस चैम्बर लि०, आगरा द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक हित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त चैम्बर को गुड़ में अग्रिम संविदाओं के बारे में, 10 अगस्त, 1973 से लेकर 9 अगस्त, 1974 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित है) की एक वर्ष की कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है ।

2 एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त चैम्बर ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जायें ।

[फा० सं० 12(7)-आई०टी०/73]

New Delhi, the 7th August, 1973

S.O. 2357.—The Central Government, in consultation with the Forward Markets Commission, having considered the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Agra Merchants' Chamber Ltd., Agra, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest to do so, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Chamber for a further period of one year from the 10th August, 1973 upto the 9th August, 1974 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Chamber shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(7)-IT/73]

का० आ० 2358.—केन्द्रीय सरकार, भारत के वनस्पति विनिर्माता संगम मुम्बई द्वारा मान्यता के पुनर्नवीकरण के लिये अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन दिये गये आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग से परामर्श करके, विचार कर लेने पर, और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक हित में भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संगम को मूंगफली के तेल की अग्रिम संविदाओं की बाबत, 10 अगस्त, 1973 से लेकर 9 अगस्त, 1974 तक, जिसमें ये दोनो दिन सम्मिलित है, एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है ।

2 एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त संगम वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निदेशों का अनुपालन करेगा ।

[सं० 12(6)-आई०टी०/73]

यू० एस० राणा, संयुक्त निदेशक

S.O. 2358.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1972 (74 of 1952) by the Vanaspati Manufacturers' Association of India, Bombay, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of one year from the 10th August, 1973 to the 9th August, 1974, both days inclusive, in respect of forward contracts in groundnut oil.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(6)-IT/73]

U. S. RANA, Joint Director

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

बम्बई, ... 1973

विषय.—सर्वश्री कान्ति लाल एंड कं. (बम्बई), 325, नर्सी नाथ स्ट्रीट, बम्बई को 15170 रुपये के लिए जारी किए गए लाइसेंस सं. पी./ई/0205175 दिनांक 6-12-1971 (मुद्रा विनिमय प्रयोजन प्रति) को रद्द करना ।

का. आ. 2359.—सर्वश्री कान्ति लाल एंड कं. (बम्बई) 325, नर्सी नाथ स्ट्रीट, बम्बई-9 की संस्थापित आयातक योजना के अन्तर्गत

ईराक से खजूरों के आयात के लिए 15170 (पन्द्रह हजार एक सौ सत्तर रुपये मात्र) के लिए लाइसेंस सं. पी/ई/0205175, दिनांक 6-12-71 प्रदान किया गया था ।

उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है ।

आगे यह बताया गया है कि उक्त लाइसेंस को बम्बई सीमा-शुल्क के पास पंजीकृत कराया गया था ।

अपने दावे के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है ।

मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस सं. पी/ई/0205175 दिनांक 6-12-71 की मुद्रा विनिमय प्रयोजन प्रति की मूल प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक फर्म को लाइसेंस की अनुलिपि जारी की जानी चाहिए ।

भूल मुद्रा विनिमय प्रयोजन प्रति को रद्द किया जाता है ।

[संख्या 213/21बी. 4/656824/एस. ए. 72/ई. आई. 3

एस. पी. दीवान, उप-मुख्य नियंत्रक,

Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports

ORDER

Bombay, the 1973

Subject : Cancellation of licence No. P/E/0205175 dt. 6-12-1971 for Rs. 15170/- (Exchange purpose copy) issued to M/s. Kantilal & Co., (Bombay) 325, Narsi Natha St., Bombay.

S.O. 2359.—M/s. Kantilal & Co., (Bombay) 325 Narsi Natha St, Bombay-9 has been granted licence No. P/E/ 0205175 dt. 6-12-1971 for Rs. 15170/- (Fifteen Thousand One Hundred and Seventy only) for import of Dates from Iraq under established Importers Scheme.

They have applied for duplicate Exchange Purpose Copy of the said licence on the ground that the original exchange purpose copy of licence has been lost/misplaced.

It is further stated that the said original licence is registered with the Bombay Customs.

In support of their claim the applicant have filed an affidavit. I am satisfied that the original copy of Exchange Purpose copy of licence No. P/E/0205175 dt. 6-12-1971 has been lost/misplaced and direct that the duplicate of the licence should be issued to the applicant firm. The original Exchange Purpose Copy if cancelled.

[No. 213/21B-4/65684/S.A. 72/E.I. 3/E.A.K. 2594]

S. P. DIWAN, Dy. C.C.I. & E.

संयुक्त-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

(केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

आदेश

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1973

का. आ. 2360.—सर्वश्री ओरियन्टल कार्पोरेशन, मोहाली, जिला रोपड़ को कायल में जस्तेदार पट्टियों के आयात के लिए 1,40,427 रु. का एक आयात लाइसेंस संख्याः पी/यू/2688998/सी, दिनांक 1-1-73 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने आयात नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैंड बुक, 1972-73 की कंडिका 318 जिसे परिशिष्ट 8 के साथ पढ़ें के अन्तर्गत अपेक्षित एक एक शपथ-पत्र दाखिल किया है जिस में उन्होंने बताया है कि लाइसेंस संख्याः पी/यू/2688998/सी, दिनांक 1-1-73 मूल्य 1,40,427 की सीमाशुल्क कार्यसम्बन्धी प्रति बिना पंजीकृत कराए और बिलकुल उपयोग किए बिना ही खो गई/ अस्थानस्थ हो गई है ।

2. मैं संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है ।

3. धतन यथा संशोधित आयात व्यापार नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7/12/1955 की धारा 9 (सी) के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर उपर्युक्त लाइसेंस संख्याः पी/यू/2688998/सी, दिनांक 1-1-73 मूल्य 1,40,427 (केवल सीमाशुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति) को एतद्द्वारा किया जाता है ।

4. आवेदक को अब आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रिया विधि हैंड बुक, 1972-73 की कंडिका 318(4) में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार लाईसेंस की अनुलिपी सीमाशुल्क कार्य सम्बन्धी प्रति जारी की जा रही है ।

[संख्या हैंडी/27/जे.एस-72/एस.सी-3/सी.एल.ए.]

Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports

(Central Licensing Area)

ORDER

New Delhi, the 24th February, 1973

S.O. 2360.—M/s. Oriental Industrial Corporation, Mohali, Distt. Ropar were granted import licence No. P/U/2688998/ C dated 1-1-73 for Rs. 1,40,427/- for import of Galvanised Strips in Coils. They have filed an affidavit as required under para. 318 read with appendix 8 of Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure, 1972-73 wherein they have stated that Customs Purposes copy of licence No. P/U/2688998 dated 1-1-73 for Rs. 1,40,427 has been lost/misplaced without having been utilised at all.

2. I am satisfied that the Customs Purposes copy of the said licence have been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under subject Clause 9(C) in the Import Trade Control Order 1955 dt. 7-12-55 as amended upto date, the said licence No. P/U/ 2688998 (Customs Purposes copy only) dated 1-1-73 for Rs. 1,40,427 is hereby cancelled.

4. The applicant is now being issued a duplicate Customs Purposes Copy of the licence in accordance with the provisions of para. 318(4) of Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1972-73.

[File No. Handi|27|JS-72|SC-III|CI.A]

आदेश

का. आ. 2361.—सर्वश्री प्रीमियर इन्डस्ट्रीज मुबारकपुर, जिला रोपड़ (पंजाब) को कायल में जस्तेदार पट्टियों के आयात के लिए 1,00,000 रु. का आयात लाइसेंस संख्याः पी/2688999/सी, दिनांक 1-1-73 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने आयात नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैंड बुक 1972-73 की कंडिका 318 जिसे परिशिष्ट 8 के साथ पढ़ें के अन्तर्गत अपेक्षित एक शपथपत्र दाखिल किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि लाइसेंस संख्याः पी/यू/2688999/सी, दिनांक 1-1-73 मूल्य 1,00,000 रु. की सीमाशुल्क कार्यसम्बन्धी तथा मुद्रा विनिमय प्रतियां बिना पंजीकृत कराए और बिलकुल उपयोग किए बिना ही खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं ।

2. मैं संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क कार्यसंबंधी तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं ।

3. अधतन यथा संशोधित आयात व्यापार नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9(सी) के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर उपर्युक्त लाइसेंस संख्या : पी/यू/2688999/सी, दिनांक 1-1-73 मूल्य 1,00,000 की सीमाशुल्क कार्यसंबंधी तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

4. आवेदक को अब आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैंड बुक, 1972-73 की कंडिका 318(4) में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां जारी की जा रही हैं।

[संख्या हैंडी/27/जे. एस-72/एस. सी.-3/सी. एल. ए.]

ORDER

S.O. 2361.—M/s. Premier Industries, Mubarakpur, Distt. Ropar (Punjab) were granted import licence No. P/U/2688999/C dated 1-1-73 for Rs. 1,00,000 for import of Galvanised Strips in Coils. They have filed an affidavit as required under para. 318 read with appendix. 8 of Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure, 1972-73 wherein they have stated that both copies of licence i.e. Customs Purposes as well as Exchange Control copy of licence No. P/U/2688999/C dated 1-1-73 for Rs. 1,00,00 have been lost/misplaced without having been utilised at all.

2. I am satisfied that the both original Customs Purposes and Exchange Control copy of the said licence have been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under subject Clause 9(C) in the Import Trade Control Order 1955 dt. 7-12-55 as amended upto date, the said licence No. P/U/2688999/C dated 1-1-73 for Rs. 1,00,000 Customs Purposes as well as Exchange Control copy is hereby cancelled.

4. The applicant is now being issued a duplicate of both Customs Purposes as well as Exchange Copy of the licence in accordance with the provisions of para. 318(4) of Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1972-73.

[File No. Handi|27|JS-72|SC-III|CLA]

आदेश

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1973

का. आ. 2362.—सर्वश्री नेशनल टेप कं., फिरोजपुर रोड, लुधियाना को 20,775 रु. के लिए एक आयात लाइसेंस सं. पी/एल/26/9890/सी-एक्स एक्स-38-डी-31-32 ए. 163 दिनांक 25-3-71 प्रदान किया गया था। अब उन्होंने लाइसेंस की अनुलिपि (सीमाशुल्क निकासी प्रति) के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उसकी मूल प्रति सीमाशुल्क कार्यालय बम्बई में पंजीकृत कराने के बाद और 10578 रु. तक उपयोग करने के बाद खो गई है।

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

3. अद्यतन यथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9(सी) के अंतर्गत मेरे लिए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 20755 रु. मूल्य के उक्त लाइसेंस सं. पी/एल-26/9890-सी-एक्स एक्स-38-डी-31-32 ए. 163 दिनांक 24-3-71 (सीमाशुल्क निकासी प्रति) को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

4. अब आवेदक को इस लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि जारी की जा रही है जो आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रिया विधि हैंड बुक, 1972-73 के पैरा 318(4) की व्यवस्था के अनुसार पुनर्वैधीकरण की तिथि से 6 महीने के लिए और आगे पुनर्वैध की जा रही है।

[सं. इंजी. 75/ओ. डी.-70/एस सी. 1/सी. एल ए.]

ए. एल. भल्ला, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 9th April, 1973

S.O. 2362.—M/s. National Tape Co., Ferozepore Road, Ludhiana were granted import licence No. P/L/2619890/C/XX/38/D/31-32A, 163 dated 25-3-71 for Rs. 20755. They have applied for duplicate licence (Customs purposes copy) on the ground that original copy thereof has been lost after having been registered at Bombay Custom House and utilised upto Rs. 10578.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the original custom copy of the above said licence has been lost/misplaced.

3. In exercise of powers conferred on me under subject Clause 9(O) in the Import Trade Control Order 1955 dated 7-12-55 as amended upto date, the said licence No. P/L/2619890/C/XX/38|D|31-32A dated 25-3-71 for Rs. 20755 (Customs Purposes Copy) is hereby Cancelled.

4. The applicant is now being issued a duplicate of Customs Purposes copy of this licence which is being revalidated further for six months from the date of revalidation, in accordance with the provision of para 318(4) of Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure 1972-73

[F. No. Engg. 75/O.D. 70/SC. I/CLA 65]

A. L. BHALLA,
Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

बम्बई, 15 फरवरी, 1973

विषय :—सर्वश्री ऋद्धि सिद्धि इंजीनियरिंग वर्क्स, एम. पी शाह म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल इस्टेट, जामनगर को 8000 रु. के लिए जारी किए गए लाइसेंस सं. पी/सी-172/657 दिनांक 6-5-72 की सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को रद्द करने के लिए आदेश।

का. आ. 2363.—सर्वश्री ऋद्धि सिद्धि इंजीनियरिंग वर्क्स को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से इस आदेश के दूसरी ओर प्रदर्शित मदों के आयात के लिये लाइसेंस अवधि अप्रैल/मार्च 1972 के लिए 8000 रु. मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं. पी/सी-172/657 दिनांक 6-5-1972 प्रदान किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रतियां खो गई हैं या अस्थानस्थ हो गई हैं। यह भी उल्लेख किया गया कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति किसी सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं कराई थी और उनका उपयोग नहीं किया था।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने स्टाम्प कागज पर नगर मजिस्ट्रेट के सामने विधिवत् साक्ष्यांकित एक शपथ पत्र दाखिल

किया है। मैं संतुष्ट हूं कि मूल लाइसेंस सं. पी/सी/1721657 दिनांक 6-5-1972 खो गया है या अस्थानस्थ हो गया है और निदेश देता हूं कि लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपियां आवेदक को जारी की जानी चाहिए। मूल लाइसेंस सं. पी/सी/1721657 दिनांक 6-5-72 को रद्द किया जाता है।

[सं. 1/73—मि. सं. ए यू-पाल/ए एम. 73/राजकोट से जारी]

OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

ORDER

Bombay, 15th February, 1973

Subject :—Order for cancellation of Customs Purpose copy and Exchange Control Purpose copy of licence No. P/C/1721657 dated 6-5-1972 for Rs. 8000 issued in favour of M/s. Riddhi Siddhi Engineering Works, M. P. Shah Municipal Industrial Estate, Jamnagar.

S.O. 2363.—Messrs. Riddhi Siddhi Engineering Works, Jamnagar was granted the import licence No. P/C/1721657 dated 6-5-1972 for Rs. 8000 for import of items shown on the reverse of this order for the licensing period April/March, 1972 from G.C.A. They have applied for duplicate copies of Customs and Exchange control purpose of the above licence on the ground that the original Customs and Exchange purpose copies of the licence have been lost or misplaced. It is further stated that the original Customs/Exchange Control purpose copy of the licence was not registered with any Customs House and not utilised.

In support of this contention, the applicant has filed an affidavit on stamped paper duly attested before the City Magistrate. I am satisfied that the original licence No. P/C/1721657 dated 6-5-1972 has been lost or misplaced and direct that a duplicate Customs purpose copy and Exchange Control Purpose copy of the licence should be issued to the applicant. The original licence No. P/C/1721657 dated 6-5-1972 is cancelled.

[No. 1/73—Issued from file No. AU-POL/AM 73/Rajkot]

आदेश

बम्बई, 27 फरवरी, 1973

विषय: सर्वश्री नन्दा ब्रास एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, 60/61, दिग्विजय प्लाट, जाम नगर के नाम में 8,000 रुपये के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी/सी/1721953, दिनांक 21-7-72 की सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति को रद्द करना।

का. आ. 2364.—सर्वश्री नन्दा ब्रास एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जामनगर को अप्रैल-मार्च 1972 लाइसेंस अवधि के लिए सामान्य मुद्रा क्षेत्र से प्रस्तुत आवेदन के पीछे दिखाई गई मदों के आयात के लिए 8000 रु० का एक आयात लाइसेंस संख्या: पी/सी/1721953 दिनांक 21-7-72 स्वीकृत किया गया था उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति खो गई है। आगे यह बताया गया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति किसी भी सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं करवाई गई थी और उसका बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया था।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी पब्लिक के सम्मुख विधिवत साक्ष्यांकित स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस संख्या पी/सी/1721953 दिनांक 21-7-72 की मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि आवेदक को लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति जारी की जानी चाहिए। मूल लाइसेंस संख्या पी/सी/1721953 दिनांक 21-7-72 को रद्द किया जाता है।

[सं० 2/73 मिसिल संख्या एयू-पाल/ए एम-73/राज कोट से जारी

ह० अपठनीय

उप-मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात,

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

ORDER

Bombay, the 27 February, 1973

Subject :—Order for cancellation of Customs purpose copy of licence No. P/C/1721953 dated 21-7-72 for Rs. 8000 issued in favour of M/s. Nanda Brass and Plastic Products, 60/61 Digvijay Plot, Jamnagar.

S.O. 2364—M/s. Nanda Brass and Plastic Products, Jamnagar was granted the import licence No.P/C/1721953 dated 21-7-72 for Rs. 8000 for import of items shown on the reverse of this order for the licensing period April/March-1972 from G.C.A. They have applied for duplicate copy of Customs purpose copy of the above mentioned licence on the ground that the original Customs purpose copy of the licence has been lost. It is further stated that the original Customs purpose copy of the licence was not registered with any customs House and not utilised.

In support of this contention, the applicant has filed on affidavit on stamped paper duly attested before the Notary Public. I am satisfied that the original licence No. P/C/1721953 dated 21-7-72 has been lost and direct that a duplicate customs purpose copy of the licence should be issued to the applicant. The Original licence No. P/C/1721953 dated 21-7-72 is cancelled.

[No. 2/73—Issued from file No. AU-POL/AM 73/Rajkot]

Sig. illegible

Dy. Chief Controller of Imports and Exports,
for Joint Chief Controller of Imports and Exports.

मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 मई, 1973

का. आ. 2365.—सर्वश्री दि इंडिया सिमेंट्स लि., मद्रास को इस्पात कास्टिंग्स के विनिर्माण के लिए लाइसेंसधारी की फैक्टरी में लगाई गई मशीनों के लिए अनुमेय फालतू पुर्जों के आयात के लिए पश्चिम जर्मनी क्रेडिट के अन्तर्गत, 1,09,000 रुपये के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी./डी./2181872, दिनांक 25-3-71 प्रदान किया गया था। यह लाइसेंस जारी किए जाने की तारीख से 12 माह के लिए वैध था और बाद में उसे 31-12-72 तक पुनर्वैध किया गया था। उन्होंने सीमाशुल्क और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन के लिए लाइसेंस की अनुलिपि प्रतियों के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस खो गया है। पार्टी ने यह बताया है कि लाइसेंस मुद्रा सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत था और उसका आंशिक उपयोग किया गया था।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने नियमों के अनुसार यथा अपेक्षित आवश्यक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि इस लाइसेंस संख्या पी/डी/2181872-एस/जी/एन/38/एच/31-32/आर एम-1 दिनांक 25-3-71 की मूल प्रतियां खो गई हैं और उक्त लाइसेंस की मूल प्रतियां उनको जारी की जानी चाहियें। मूल सीमाशुल्क तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां एतद्द्वारा रद्द की जाती हैं। अनुलिपि सीमाशुल्क तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां अलग से जारी की जा रही हैं।

[संख्या एस सी/45/स्पेयर्स/70-71/आर एम-1]

ए. के. सरकार, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports

ORDER

New Delhi, the 6th June, 1973

S.O. 2365.—M/s. The India Cements Ltd., Madras were granted import licence No. P/D/2181872 dated 25-3-1971 for the import of permissible spare parts for the machines installed in the licence holders factory for the manufacture of steel castings valued at Rs. 1,09,000 under W. German Credit. This licence was valid for 12 months from the date of issue and was subsequently revalidated upto 31-12-1972. They have requested for issue of duplicate copies of the licence for Customs and Exchange Control purposes on the ground that both copies of the original licence have been lost. The party have stated that the licence was registered with the Madras Customs House and utilised party.

In support of their contention, the applicant has furnished necessary affidavit as required under the rules. The undersigned is satisfied that the original copies of this licence No. P/D/2181872/S/GN/38/H/31.32/RMI dated 25-3-1971 have been lost and directs that duplicate copies of the said licence should be issued to them. The original custom & Exchange control copies are hereby cancelled. The duplicate customs & Exchange Control Copies are being issued separately.

[No. SC/45/Spares/70.71/RMI]

A. K. SARKAR,
Dy. Chief Controller of Imports & Esports,
for Chief Controller of Imports & Exports.

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई 30 जुलाई, 1973

का० आ० 2366.—लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित अधिकारी को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी है उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, और उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट लोक परिसरों के संबंध में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पद नाम	लोक परिसरों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
निर्माण प्रबंधक भारी जल परियोजना अणुशक्ति कोटा (राजस्थान)।	भारी जल परियोजना कोटा राजस्थान राज्य के या उसके प्रबंधाधीन, भारी जल परियोजना (कोटा) आवास कालोनी अणुशक्ति, नामक परिसरों के संबंध में।

[फा० सं० 13/2/73-(एच)]

तरलोक सिंह, अवर सचिव।

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay, the 30th July, 1973

S.O. 2366.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of a gazetted officer of Government, to be the estate officer for the purposes of the said Act, and the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the the said Table.

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
1	2
Construction Manager, Heavy Water Project, Anushakti, Kota, (Rajasthan).	In respect of premises known as Heavy Water Project (Kota) Housing Colony at Anushakti belonging to or under the management of the Heavy Water Project, at Kota, Rajasthan State.

[F. No. 13/2/73-(H)]

TARLOK SINGH, Under Secy.

औद्योगिक विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1973

का० आ० 2367.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) नियम 1955 के नियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि मानक चिह्न जिनकी डिजाइन और शाब्दिक विवरण तत्संबंधी भारतीय मानकों के शीर्षकों सहित नीचे अनुसूची में दिए गए हैं भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किए गए है:

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित ये मानक चिह्न उनके आगे दी हुई तिथियों से लागू हो जाएंगे।

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद का वर्ग	सम्बद्ध भारतीय मानक की पद-संख्या और शीर्षक	भारतीय मानक चिह्न की डिजाइन का शाब्दिक विवरण	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS 834	होजरी के लिए खुदरंग सूती धागा	आई एस : 834-1970 होजरी के लिए खुदरंगसूती धागे की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमे 'आई एस आई' शब्द होते है स्तम्भ (2) में दिखाई शैली और अनुपात मे तैयार किया गया है और जैसा दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी हुई है।	1 जुलाई 1973

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	आई एस : 4663	जूता उद्योग के लिए रबड़ के बने स्थायी चेप पदार्थ	आई एस : 4663-1968 जूता उद्योग के लिए रबड़ के बने स्थायी चेप पदार्थ की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'आई एस आई' शब्द होते हैं स्तम्भ (2) मे दिखाई गई शैली और अनुपात मे तैयार किया गया है और जैसा दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी हुई है ।	1 मई 1973
3.	आई एस : 6595	खेती के कार्यों के लिए साफ ठंडे और ताजे पानी के क्षैतिज अप-केन्द्रीय पम्प	आई एस :6595-1972 खेती के कार्यों के लिए साफ, ठंडे और ताजे पानी के क्षैतिज अपकेन्द्रीय पम्पो की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 'आई एस आई' शब्द होते हैं स्तभ (2) मे दिखाई गई शैली और अनुपात मे तैयार किया गया है और जैसा दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी हुई है ।	16 अप्रैल 1973

[सं० सी एमडी/13:9]

डी दास० गुप्ता, उप-महानिदेशक ।

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, SCIENCE AND TECHNOLOGY
INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 26th July, 1973

S O.2367.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution bereby notifies that the Standard Mark(s),design(s) of which together with the verbal description of the, design(s) and the title(s) of the relevant Indian Standard(s) /are given in the Schedule here to annexed, have been specified.

These Standard Mark(s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from the dates shown against each:

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark	Date of Effect
1	2	3	4	5	6
1.	I S : 834	Cotton yarn, grey, for hosiery.	I S: 834-1970 Specification for cotton yarn, gray for hosiery **(first revision).**	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting fo letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2), the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1st July, 1973
2.	I S: 4663	Permanent rubber-based adhesives for footwear industry.	IS : 4663-1968 Specification for permanent rubber-based adhesives for footwear industry.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as included in Col. (2), the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	1st may, 1973
3.	I S : 6595	Horizontal centrifugal pumps for clear, cold, fresh water for agricultural purposes.	IS : 6595-1972 Specification for horizontal centrifugal pumps for clear, cold, fresh water for agricultural purposes.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2), the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.	16th Apirl, 1973

[No. CMD/13:9]

D.DAS GUPTA, Deputy Director General

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1973

का.आ. 2368.—यतः भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार ने मैसूर सरकार के परामर्श से डा० एच० जी० सत्तूर, जिन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं के निदेशालय, बंगलौर के संयुक्त निदेशक (चिकित्सा) डा० वाई० पी० रुद्रप्पा को 28 मई, 1973 से भारतीय चिकित्सा परिषद का सदस्य मनोनीत किया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या 5-13/59/चि० 1 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में "धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन मनोनीत" शीर्ष के अंतर्गत क्रम संख्या 12 पर उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जाएं :—

"डा० वाई० पी० रुद्रप्पा,
संयुक्त निदेशक (चिकित्सा)
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन सेवाओं का निदेशालय,
बंगलौर"

[सं.बी. 11013/2/73 एम. पी. टी.]

कु० सती बालकृष्णा, अवर सचिव।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING
(Department of Health))

New Delhi, the 6th August, 1973

S.O. 2368.—Whereas the Central Government has, in pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) nominated in consultation with the Government of Mysore, Dr. Y. P. Rudrappa, Joint Director (Medical), Directorate of Health and Family Planning Services, Bangalore, to be a member of the Medical Council of India with effect from the 28th May, 1973 vice Dr. H. G. Sattur resigned;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 5-13/59-MI, dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated under clause (a) of sub-section (1) of section 3", for the entry against serial No. 12, the following entry shall be substituted, namely :—

"Dr. Y. P. Rudrappa,
Joint Director (Medical),
Directorate of Health and Family Planning,
Services, Bangalore."

[No. V. 11013/2/73-MPT]

KUM. SATHI BALAKRISHNA, Under Secy.

संचार विभाग

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1973

का. आ. 2369.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खण्ड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने रामनद टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-9-73 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं. 5-18/73-पी एच बी]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(P & T Board)

New Delhi, the 3rd August, 1973

S.O. 2369.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-9-1973 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in RAMNAD Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-18/73-PHB]

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1973

का. आ. 2370.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च,, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खण्ड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने देवरिया टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-9-73 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं. 5-2/73 पी. एच बी.]

पी. सी गुप्ता, सहायक महानिदेशक (पी एच बी)

New Delhi, the 9th August, 1973

S.O. 2370.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-9-1973 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in DEORIA Telephone Exchange, U.P. Circle.

[No. 5-2/73-PHB]

P. C. GUPTA, Assistant Director General (PHB)

नौवहन और परिवाहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1973

का० आ० 2371.—भारतीय व्यापार नौवहन (नाविक रोजगार कार्यालय, कलकत्ता) नियम, 1954, के नियम 5 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए कलकत्ता पत्तन पर नाविक रोजगार बोर्ड (गृह व्यापार) नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

1. नौवहन के उपमहानिदेशक, नाविक रोजगार कार्यालयों के प्रभारी	अध्यक्ष
2. निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय, कलकत्ता	सदस्य सचिव
3. श्री एम के तन्ना 4. कल्यान जी० ए० लोबो	पोतस्वामियों के प्रतिनिधि सदस्य
5. श्री विजय मुखर्जी 6. श्री रबीन्द्रनाथ महाचार्य	नाविकों के प्रतिनिधि सदस्य

[फ० सं० 15-एम टी (1)/73]

(बी० वि० सुब्राह्मण्यम्, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Transport Wing)

New Delhi-1, the 28th July, 1973

S.O. 2371.—In pursuance of rule 5 of the Indian Merchant Shipping (Seamen's Employment Office, Calcutta) Rules, 1954, the Central Government hereby appoints a Seamen's Employment Board (Home Trade) at the port of Calcutta for a period of two years with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette consisting of the following members, namely:—

1. Deputy Director General of Shipping, Incharge of Seamen's Employment Offices	Chairman.
2. Director, Seamen's Employment Office, Calcutta.	Member-Secretary
3. Shri M. K. Tanna	Members' representing Shipowners.
4. Capt. G.A. Lobo	
5. Shri Bejoy Mukherjee.	Member representings Seafarers.
6. Shri Rabindra Nath Bhattacharjee	

File No. 15-MT(1)/73]

V.V. SUBRAHMANYAM, Deputy Secretary

निर्माण और आवास मंत्रालय
(दिल्ली विकास प्राधिकरण)

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1973

सार्वजनिक सूचना

का. आ. 2372.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है जिसे सार्वजनिक सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है। इस संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस ज्ञापन के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास भवन, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें। जो व्यक्ति अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दें वे अपना नाम एवं पूरा पता भी लिखें।

संशोधन.—"लगभग 10.9 हैक्टर (26.81 एकड़) का क्षेत्र जो उत्तर-पश्चिम में 64 मीटर (210') चौड़ी रिंग रोड़ तथा उत्तर-पूर्व में जी. टी. करनाल रोड़, दक्षिण-पूर्व में अयोध्या टैक्सटाइल मिल्स तथा दक्षिण-पश्चिम में रेलवे भूमि द्वारा घिरा हुआ है। उक्त क्षेत्र जोन सी-18 (त्रिपोलिया) में पड़ता है उसके भूमि उपयोग को 'औद्योगिक' से 'आवासीय' में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।"

शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्था एस्टेट, नई दिल्ली-1 में उक्त अवधि में आकर प्रस्तावित संशोधन के मानचित्रों का निरीक्षण किया जा सकता है।

[संख्या एफ. 3(220)/71-एम· पी]

हृदय नाथ फोतेदार, सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING
(Delhi Development Authority)

New Delhi, the 18th August, 1973

PUBLIC NOTICE

S.O. 2372.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhawan, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION

"An area measuring about 10.9 hect. (26.81 acres) and bounded by 64 meters (210 ft.) Ring Road in north-west, G. T. Karnal Road in north-east, Ayodhya Textile Mills in the south-east and Railway land in the south-west, in zone C-18 (Tripolia) in proposed to be changed from 'industrial use' to 'residential use'.

The plan indicating the propsed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Delhi Vikas Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi on all working days except Saturdays within the period referred to above.

[No. F. 3(220)/71-M.P.]

H. N. FOTEDAR, Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय
(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 25 मई, 1973

का० आ० 2373 यत इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त विवाद कहा गया है) श्री पी० एम० अनन्थ पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में है, के समक्ष लम्बित थे

और यतः श्री पी० एम० अनन्थ की सेवायें अब उपलब्ध नहीं रही है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 33ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० नरसिंगा राव होंगे जिनका मुख्यालय हैदराबाद होगा, श्री पी० एस० अनन्थ से उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाहियों को वापस लेती है और उन्हें उक्त विवाद के निपटान के लिये श्री टी० नरसिंगा राव, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद को इस निदेश के साथ अन्तरित करती है कि उक्त अधिकरण उसी प्रक्रम से कार्यवाहियों को अग्रसर करेगा जिस पर वे उसे अन्तरित की जाये और विधि के अनुसार उनका निपटान करेगा।

अनुसूची

क्रम सं०	विवाद के पक्षकार	न्यायनिर्णयन आदेश के निर्देश की संख्या और तारीख
1	2	3
1	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड और उनके कर्मकार।	7/21/67-एल० आर० II तारीख 30 अक्टूबर, 1967
2	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और उनके कर्मकार।	7/23/68-एल० आर० II तारीख 29 अक्टूबर, 1969
3	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड और उनके कर्मकार।	7/29/70-एल० आर० II तारीख 12 फरवरी, 1971
4	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड और उनके कर्मकार।	7/16/70-एल० आर० II तारीख 7 अप्रैल, 1971
5	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड और उनके कर्मकार।	7/21/70-एल० आर० II तारीख 7 अप्रैल, 1971
6	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड और उनके कर्मकार।	7/49/70-एल० आर० II तारीख 15 मई, 1971
7	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड और उनके कर्मकार।	एल/2112/24/71-एल०आर०II तारीख 19 अक्टूबर, 1971
8	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड और उनके कर्मकार।	एल/2112/25/71-एल०आर०II तारीख 22 अक्टूबर, 1971
9.	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड और उनके कर्मकार।	एल/2112/26/71-एल०आर०II तारीख 25 नवम्बर, 1971
10	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड और उनके कर्मकार।	एल/2112/47/71-एल०आर० II तारीख 28 मार्च, 1972
11	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड और उनके कर्मकार।	एल/21012/6/72-एल०आर० II तारीख 5 जून, 1972
12	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड और उनके कर्मकार।	7/2/70-एल० आर० II तारीख 20 अप्रैल, 1972
13	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और उनके कर्मकार।	एल/2112/48/71-एल०आर०II तारीख 28 जून, 1972
14	महा-प्रबन्धक, आन्ध्र बैंक लिमिटेड, हैदराबाद और उनके कर्मकार।	23/28/70-एल० आर० III तारीख 23 जनवरी, 1971
15	क्षेत्रीय निदेशक, इंडियन एयर लाइन्स मद्रास और उनके कर्मकार।	एल/11011/3/72-एल०आर० III तारीख 12 मई, 1972
16	मुख्य अभियन्ता, एयरफोर्स एकडेमी प्रोजेक्ट, पैगा पैलेस, सिकन्दराबाद और उनके कर्मकार।	3/2/70-एल० आर० I तारीख 22 अप्रैल, 1971
17	नैशनल मिनरल्स डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की दोनिमलाई आयरन् और प्रोजेक्ट और उनके कर्मकार।	एल/26011/6/71-एल० आर०I तारीख 25 नवम्बर, 1971
18	दि कांटिनेन्टल कंस्ट्रक्शन (प्राइवेट) लि० अभियन्ता और ठेकेदार आउटर हार्बर प्रोजेक्ट विशाखापटनम और उनके कर्मकार।	एल०/34011/8/72-पी० एंड डी० तारीख 19 जनवरी 1973

लम्बित केन्द्रीय सरकार प्रकीर्ण अर्जियां

धारा 33/2/ख .

1	2	3	4
1	एम० पी० सं० 205/66	प्रबन्धक मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी बनाम लिमिटेड कोठागुडेम।	श्री उदुरकोंडा मल्लाईयाह, कोल फिलर, कल्याण खानी संख्या 1, माडामारी डिवीजन।
2.	एम० पी० सं० 206/66	प्रबंधक मंडल सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी बनाम लिमिटेड, कोठागुडेम।	श्री धेंगाला रमैयाह कोल फिलर, कल्याण खानी सं० 1, माडामारी डिवीजन।
3	एम० पी० सं० 207/66	प्रबंधक मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी बनाम लिमिटेड, कोठागुडेम।	श्री आईदारामुलु, टैम्मर, कल्याण खानी सं० 1, डिवीजन।
4.	एम० पी० 208/66	प्रबन्ध मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी बनाम लिमिटेड कोठागुडेम।	श्री एनागुन्डुला, नारसैयाह कोल फिलर, खाई-1, कल्याण खानी सं० 1, माडामारी डिवीजन।
5	एम० पी० सं० 214/66	प्रबन्धक मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज, कम्पनी बनाम लिमिटेड, कोठागुडेम।	श्री कोलिपाकापेडा मल्लाईयाह कोल फिलर, कल्याण खानी सं० 1, माडामारी डिवीजन।
6.	एम० पी० सं० 61/67	प्रबन्धक मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज, कम्पनी बनाम लिमिटेड, बेल्लमपल्ली।	श्री मोतीलाल शर्मा, खनन सरदार, सोमागुडेम माइन्स, बेल्लमपल्ली।
7.	एम० पी० सं० 17/69	प्रबन्ध मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी बनाम लिमिटेड, कल्याण खानी डामारी डिवीजन	श्री पी० बालराम, भूतपूर्व लारी चालक, प्रभागीय भंडार, माडामारी डिवीजन।
8.	एम० पी० सं० 106/72	प्रबन्ध मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी बनाम लिमिटेड, कोठागुडेम।	श्री के० एम० काथा राव, लिपिक, वी० के० सं० 7, इन्कलाईन, कोठागुडेम, डिवीजन कोठागुडेम।
9.	एम० पी० सं० 107/73	प्रबंध मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी बनाम लिमिटेड, कोठागुडेम।	श्री बी० के० स्वामीदास लिपिक, वी० के० सं० 7, कोठागुडेम डिवीजन, कोठागुडेम।

1	2	3		4
10	एम०पी० म० 122/72	प्रबंध मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, बेल्लमपल्ली डिवीजन, बेल्लमपल्ली ।	बनाम	श्री सेग्गाम जान, कोल फिलर, मोर्गोन की खाई, बेल्लमपल्ली डिवीजन ।
11	एम० पी० सं० 126/72	प्रबंध मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज, कम्पनी लिमिटेड, रामागुडम डिवीजन-1, रामागुडम ।	बनाम	श्री जंगरेला मल्लाईयाह, कोल फिलर, गोदावरी खानी 2, रामागुडम डिवीजन ।
12	एम० पी० सं० 131/72	प्रबंध मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज, कम्पनी लिमिटेड, रामागुडम डिवीजन, रामागुडम ।	बनाम	श्री थाली रंगाईयाह, कोल-कट्टर गोदावरी खानी 7, रामागुडम डिवीजन-11
13	एम० पी० सं० 132/72	प्रबंध मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडेम ।	बनाम	श्री जंगम राजीरु कोल फिलर, वी० के० सं० 7, कोठागुडेम डिवीजन ।
14	एम० पी० सं० 1/73	प्रबंध मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज, कम्पनी लिमिटेड, बेल्लमपल्ली ।	बनाम	श्री एल्काटूरी कोमारियाह, फिलर, गैंग सं० 18, शान्ति खानी, बेल्लमपल्ली डिवीजन ।
15	एम० पी० सं० 2/73	प्रबंध मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, बेल्लमपल्ली ।	बनाम	श्री सलिगाति नरसाईयाह, फिलर, गैंग सं० 18, शान्ति खानी, बेल्लमपल्ली डिवीजन 1
16.	एम० पी० सं० 3/73	प्रबंध मंडल सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडेम ।	बनाम	श्री डी० वी० प्रसादा राव, लिपिक, अभिकर्त्ता का कार्यालय, कोठागुडेम डिवीजन, रुद्रारामपुर ।
17.	एम० पी० सं० 5/73	प्रबंध मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, रामागुडम डिवीजन 1, रामागुडेम ।	बनाम	श्री एम० सदाशिवा राव, चपरासी, प्रभागीय कार्मिक अधिकारी का कार्यालय, रामागुडेम ।
18.	एम० पी० स० 8/73	प्रबंध मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, कल्याण खानी, मांडामारी डिवीजन ।	बनाम	श्री थुम्माराजीरु, साधारण मजदूर, कल्याण खानी कर्मशाला, मांडामारी डिवीजन ।
19.	एम० पी० स० 9/73	प्रबंध मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज, कम्पनी लिमिटेड, कल्याण खानी, माडामारी डिवीजन ।	बनाम	श्री बिकरुकरी राजाम, साधारण मजदूर, कल्याण कर्मशाला, मांडामारी डिवीजन ।
धारा 33(3) (ख):				
1.	एम० पी० स० 211/66	प्रबंध मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडेम ।	बनाम	श्री के० पापा राव, हालर चालक, कल्याण खानी सं० 4, मांडामारी डिवीजन ।
2.	एम० पी० सं० 212/66	प्रबंध मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडेम ।	बनाम	श्री कोदाम नरसाईयाह, कोल कट्टर कल्याण खानी, सं० 1, माडामारी डिवीजन ।
3.	एम० पी० सं० 213/66	प्रबंध मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडेम ।	बनाम	श्री कोला एल्लईयाह, कोलफिल्लर, गैंग सं० 3, कल्याण खानी सं० 1, मांडामारी डिवीजन ।
धारा 33 (क)				
1.	एम० पी० सं० 167/68	मुख्य अस्पताल, कोठागुडेम के चिकित्सीय विभाग के श्री मोहम्मद शरीफ और अन्य 6 कर्मकार ।	बनाम	प्रबंध मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडेम ।
2	एम० पी० सं० 78/72	श्री बी० गंगाराम, उप-अध्यक्ष, एस० सी० श्रमिक संघ, बेल्लमपल्ली ।	बनाम	प्रबन्ध मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड बेल्लमपल्ली डिवीजन, बेल्लमपल्ली ।
3	एम० पी० सं० 125/72	श्री सेग्गाम जान, कोल फिलर जी० सं० 8 ख, मोरगोन्स पिट, मार्फत ए० सी० श्रमिक संघ, बेल्लमपल्ली ।	बनाम	प्रबंध मंडल, सिंगरेनी कोयलयरीज कम्पनी लिमिटेड बेल्लमपल्ली डिवीजन, बेल्लमपल्ली ।
4.	एम० पी० सं० 135/72	श्री गोलिका नरसाइयाह, कोल फिलर, मोरगिंस पिट, मार्फत, एम० सी० श्रमिक संघ, बेल्लमपल्ली ।	बनाम	प्रबंध मंडल, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, बेल्लमपल्ली डिवीजन, बेल्लमपल्ली ।
5.	एम० पी० सं० 6/73	1. श्री सलिगाति नारसाइयाह, 2 श्री एल्काटूरी कोमाराइयाह, कोल फिलर, शान्ति खानी मार्फत एस० सी० श्रमिक संघ, बेल्लमपल्ली ।	बनाम	प्रबंध मंडल, सिंगरानी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, बेल्लमपल्ली डिवीजन, बेल्लमपल्ली ।

[सं० एस21025/4/73-एल० आर० 11]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour & Employment)

New Delhi, the 25th May, 1973

ORDER

S. O.2373 — WHEREAS the industrial disputes specified in the Schedule hereby annexed (hereinafter referred to as the said disputes) were pending before Shri P.S. Ananth, Presiding Officer, Central Industrial Tribunal with headquarters at Hyderabad;

AND WHEREAS Shri P.S. Ananth's services have ceased to be available;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers confe red by section 7A, and sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri T. Narasinga Rao, as the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad, withdraws the proceedings in relation to the said disputes from Shri P.S. Ananth and transfers the same to Shri T. Narasinga Rao, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Hyderabad for the disposal of the said disputes with the directions that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stages at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. No.	Parties to dispute	Reference No. and date of adjudication order
1	2	3
1.	Singareni Collieries Company Limited and their workmen.	7/21/67-LRII, dated the 30th October, 1967.
2.	Singareni Collieries Company Limited and their workmen.	7/23/68-LRII, dated the 29th October, 1969.
3.	Singareni Collieries Company Limited and their workmen.	7/29/70-LRII, dated the 12th February, 1971.
4.	Singareni Collieries Company Limited and their workmen.	7/16/70-LRII, dated the 7th April, 1971.
5.	Singareni Collieries Company Limited and their workmen.	7/24/70-LRII, dated the 7th April, 1971.
6.	Singareni Collieries Company Limited and their workmen.	7/49/70-LRII, dated the 15th May, 1971.
7.	Singareni Collieries Company Limited and their workmen.	L/2112/24/71-LRII, dated the 19th October, 1971.
8.	Singareni Collieries Company Limited and their workmen.	L/2112/25/71-I RII dated the 22nd October, 1971.
9.	Singareni Collieries Company Limited and their workmen.	L/2112/26/71-LRII, dated the 25th November, 1971.
10.	Singareni Collieries Company Limited and their workmen.	L/2112/47/71-LRII, dated the 28th March, 1972.
11.	Singareni Collieries Company Limited and their workmen.	L/21012/6/72-LRII, dated the 5th June 1972.
12.	Singareni Collieries Company Limited and their workmen.	7/2/70-LRII, dated the 20th April, 1972.
13.	Singareni Collieries Company Limited and their workmen.	L/2112/48/71-LRII, dated, the 28th June, 1972.
14.	The General Manager, Andhra Bank Limited, Hyderabad and their workmen.	23/28/70-LRIII, dated the 23rd January, 1971.
15.	The Regional Director, Indian Airlines, Madras and their workmen.	L/11011/3/72-LRIII, dated, the 12th May, 1972.
16.	The Chief Engineer, Air Force Academy Project, Paiga Palace, Secunderabad and their workmen.	3/2/70-LRI, dated the 22nd April, 1971.
17.	Donimalai Iron Ore Project of National Minerals Development Corporation Limited, P. O. Sandur and their workmen.	L/26011/6/71-LRIV, dated the 25th November, 1971.
18.	The Continental Construction (Private) Ltd., Engineers and Contractors, Outer Harbour Project; Visakhapatnam and their workmen.	L/34011/8/72-P&D, dated the 19th January, 1973.

CENTRAL GOVERNMENT MISCELLANEOUS PETITIONS PENDING

Section 33(2)(b) :

1	2	3	4
1.	M.P. No. 205/66 . . .	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem.	Vs. Shri Udurukonda Mallaiah, Coal Filler Kalyan Khani No. 1, Mandamari Division.
2.	M.P. No. 206/66 . . .	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Kothagudium.	Vs. Shri Thegala Ramaiah, Coal Filler, Kalyan Khani No. 1, Mandamari Division.
3.	M.P. No. 207/66 . . .	The Management, Singareni Collieries Kothagudem.	Vs. Shri Iyda Ramulu, Trammer, Kalyan Khani No.1, Mandamari Division.
4.	M.P. 208/66 . . .	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Kothadudem.	Vs. Sri Enagundula Narasaiah, Coal Filler, Y-1, Kalyan Khani No. 1., Mandamari Division.

1	2	3	4
5.	M.P. No. 214/66	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem.	Vs. Sri Kolipaka Peda Mallaiah, Coal Filler, Kalyan Khani No. 1, Mandamari Division.
6.	M.P. No. 61/67	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli.	Vs. Sri Motilal Sharma, Mining Sirdar, Somagudem Mines, Bellampalli.
7.	M.P. No. 17/69	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Kalyan Khani, Mandamari Division.	Vs. Sri P. Balaram, Ex-Lorry Driver, Divisional Stores, Mandamari Division.
8.	M.P. No. 106/72	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem.	Vs. Sri K.S. Kantha Rao, Clerk, V.K. No. 7 Incline, Kothagudem Division, Kothagudem.
9.	M.P. No. 107/72	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem.	Vs. Sri B. K. Swamidas, Clerk, V.K. No. 7, Kothagudem Divn., Kothagudem.
10.	M.P. No. 122/72	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Divn., Bellampalli.	Vs. Sri Seggam John, Coal Filler, Morgons Pit, Bellampalli Division.
11.	M.P. No. 127/72	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division-I, Ramagundam.	Vs. Sri Jangerla Mallaiah Coal Filler, Godavari Khani 2, Ramagundam Division.
12.	M.P. No. 132/72	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division, Ramagundam.	Vs. Sri Thati Rangaiah, Coal Cutter, Godavari Khani 7, Ramagundam Divn. II.
13.	M.P. No. 132/72	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem.	Vs. Sri Jangam Rajeeru, Coal Filler, V.K. No. 7, Kothagudium Division.
14.	M.P. No. 1/73	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli.	Vs. Sri Elkatoori Komariah, Filler, Gang No. 18, Shanti Khani, Bellampalli Division.
15.	M.P. No. 2/73	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli.	Vs. Sri Saliganti Narsaiah, Filler, Gang No. 18, Shanti Khani, Bellampalli Division.
16.	M.P. No. 3/73	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem.	Vs. Sri D.V. Prasada Rao, Clerk, Agent's Office, Kothagudem Division, Rudrampur.
17.	M.P. No. 5/73	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division-I, Ramagundam.	Vs. Sri M. Sadasiva Rao, Peon, Divisional Personnel Officer's Office, Ramagundam.
18.	M.P. No. 8/73	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Kalyan Khani, Mandamari Division.	Vs. Sri Thumma Rajeeru, General Mazdoor, Kalyan KhaniWorkshop, Mandamari Division.
19.	M.P. No. 9/73	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Kalyan Khani, Mandamari Division.	Vs. Sri Bikrukuri Rajam, General Mazdoor, Kalyan Khani Workshop, Mandamari Division.

1	2	3	4
Section 33(3) (b) :			
1. M.P. No. 211/66	. . .	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem.	Vs. Sri K. Papa Rao, Hauler Driver, Kalyan Khani No. 4, Mandamari Division.
2. M.P. No. 212/66	. . .	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem.	Vs. Sri Kodam Narsaiah, Coal Cutter, Kalyan Khani No. 1, Mandamari Division.
3. M.P. No. 213/66	. . .	The Management, Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem.	Vs. Sri Kola Ellaiah, Coal Filler, Gang No. 3, Kalyan Khani No. 1, Mandamari Division.
Section 33(A) :			
1. M.P. No. 167/68	. . .	Shri Mohd. Sherif and other 6 workmen of Medical Deptt., Main Hospital, Kothagudem.	Vs. The Management Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem.
2. M.P. No. 78/72	. . .	Shri B. Gangaram, Vice President, S. C. Workers Union, Bellampalli.	Vs. The Management, Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division, Bellampalli.
3. M.P. No. 125/72	. . .	Sri Seggam John, Coal Filler, G. No. 8B, Morgons Pit, C/o S.C. Workers Union, Bellampalli.	Vs. The Management, Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division, Bellampalli.
4. M.P. No. 135/72	. . .	Sri Gosika Narsaiah, Coal Filler, Morgans Pit, C/o S. C. Workers Union, Bellampalli.	Vs. The Management, Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division,
5. M.P. No. 6/73	. . .	1. Sri Saliganti Narsaiah, 2. Sri Elkatoori Komaraiah, Coal Fillers, Shanti Khani, C/o S.C. Workers Union, Bellampalli.	Vs. The Management, Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division, Bellampalli.

[No. L/21025/4/73-LRII.]

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1973

का० आ० 2374.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्रीपुर कोलियरी, डाकघर कालीपहाड़ी, जिला बर्दवान के प्रबन्ध-तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची–1

"क्या कर्मकारों की निम्नलिखित अनुसूची-2 में उल्लिखित कर्मकारों को श्रीपुर कोलियरी, डाकघर कालीपहाड़ी, जिला बर्दवान के प्रबन्ध-तंत्र द्वारा स्थायी बनाये जाने की मांग न्यायोचित है ? यदि हां, तो ये कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं और किस तारीख से ?"

अनुसूची–2

क्रमांक	कर्मकारों का नाम	पद संख्या
1.	श्री चाटों मिया	यू० जी० ट्रैमर
2.	श्री नूर मोहम्मद	यथोक्त
3.	श्री इब्राहिम	यथोक्त
4.	श्री अरब मिया	यथोक्त
5.	श्री सलीम	यथोक्त
6.	श्री जला अहमद	यथोक्त
7.	श्री अक्तर हुसैन	यथोक्त
8.	श्री समसुल	यथोक्त
9.	श्री सकीर	यथोक्त
10.	श्री अनवर	यथोक्त
11.	श्री वामुवर पासवान	यथोक्त
12.	श्री राम गुलाम पासवान	यथोक्त
13.	श्री चान्द्रा देव पासवान	यथोक्त
14.	श्री सोलेमान	यथोक्त
15.	श्री खैराजुद्दीन	यथोक्त

[संख्या एल/19012/107/72-एल० आर०–2]

ORDER

New Delhi, the 13th July, 1973

S.O. 2374.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Sirpur Colliery, Post Office Kalipahari, District Burdwan, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And Whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE-I

Whether the demand of the workmen for granting permanency to the workmen mentioned in Schedule-II below, by the management of Sripur Colliery, Post Office Kalipahari, District Burdwan, is justified? If so, to what relief are the workmen entitled and from what date?

SCHEDULE-II

Sl. No.	Name of workmen	Designation
1.	Shri Chaton Mia	U. G. Trammer.
2.	Shri Noor Md.	do
3.	Shri Ibrahim	do
4.	Shri Arab Mia	do
5.	Shri Salim	do
6.	Shri Jala Ahmad	do
7.	Shri Aktar Hussain	do
8.	Shri Samsull	do
9.	Shri Sabir	do
10.	Shri Anwar	do
11.	Shri Damudar Paswan	do
12.	Shri Ram Gulam Paswan	do
13.	Shri Ghandra Deo Paswan	do
14.	Shri Soloman	do
15.	Shri Sawrajuddin	do

[No. L/19012/107/72-LRII.]

आदेश

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1973

का० आ० 2375 यतः व्यास डैम प्रोजेक्ट, तलवाड़ा से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व व्यास प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट, तलवाड़ा टाउनशिप करता है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और यतः उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को, जो उसे 20 जुलाई, 1973 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम	के बीच
नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले	1. श्री सरदारी लाल, कार्यकारी अभियन्ता (कार्मिक), व्यास डैम प्रोजेक्ट, तलवाड़ा। 2. श्री कुलदीप सिंह, कार्मिक अधिकारी, व्यास डैम प्रोजेक्ट, तलवाड़ा।
कर्मचारों का प्रतिनिधित्व करने वालें	श्री संतोख सिंह, महासचिव, व्यास डैम प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट, तलवाड़ा।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री डी० पांडा, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कानपुर के मध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का एतद्द्वारा करार किया गया है।

1. विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय	क्या पम्प ड्राइवर/वाटर पम्प मैकेनिकल (डिजल और इलेकट्रिकल) वर्ग I 120—250 रु० के संशोधित वेतन मानों के लिए 1-4-71 के स्थान पर 1-1-70 से हकदार हैं ? यदि नहीं, तो वे किस अनुतोष के हकदार हैं ?
	1. व्यास डैम प्रोजेक्ट, तलवाड़ा।
2. विवाद के पक्षकारों का विवरण जिसमें प्रतिबंधित स्थापन का उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है।	2. व्यास प्रोजेक्ट, वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट, तलवाड़ा।
3. यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम।	व्यास प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट, तलवाड़ा।
4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या।	16,000
5. विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या	30

हमने यह करार भी किया कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्ध कर होगा।

मध्यस्थ अपना पंचाट तीन मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जायेगा और हम नए माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतन्त्र होंगे।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

ह० सरदारी लाल — ह० कुलदीप सिंह

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले — 25/6

ह० संतोख सिंह

25-6-73

श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले

साक्षी

1. ह० करनैल सिंह — 2. बाबू लाल

[संख्या एल० 42013/6/73-एल०आर०—3]

ORDER

New Delhi, the 1st Aug. 1973

S.O. 2375.—Whereas an Industrial dispute exists between the employers in relation to the Beas Dam Project, Talwara and its workmen represented by Beas Project Workers United Front, Talwara Township.

And, whereas the said employers and workmen have, by a written agreement, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration by the person specified therein, and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government.

Now, therefore in pursuance of sub-section (3) of section 10-A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 20th July, 1973.

AGREEMENT

(Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Name of the parties:—

Representing employers:
1. Shri Sardari Lal, Executive Engineer (Personnel), Beas Dam project, Talwara.
2. Shri Kuldip Singh, Personnel Officer, Beas Dam Project, Talwara.

Representing workmen: Shri Santokh Singh, Secretary General, Beas, Project Workers United Front, Talwara.

It is hereby agreed between the parties to refer the following Industrial dispute to the arbitration of SHRI D. PANDA, Regional Labour Commissioner (Central), Kanpur:—

(i) Specific matters in dispute:	"Whether the Pump Driver/-Water Pump Mechanical (Diesel and Electrical) Grade I are entitled to the revised scales of pay of Rs. 120–250 with effect from 1-1-70 instead of from 1-4-71? If not, to what relief are they entitled?."
(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved:	1. Beas Dam Project, Talwara. 2. Beas Project Workers United Front, Talwara.
(iii) Name of the Union, if any, representing the workmen in question:	Beas Project Workers United Front, Talwara.
(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected:	16000
(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute:	30

We further agreed that decision of the arbitrator shall be binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of three months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the parties

Sd/-Kuldip Singh

25-6-73

Sd/- Sardari Lal
Representing employers.
Sd/- Santokh Singh
Representing Workmen.
25-6-73

Witnesses :

1. Sd/- Karnail Singh. 2. Babu Lal.

[No. 2-42013/6/73-LR III]

New Delhi, the 4th August, 1973

S.O. 2376.—In pursuance of section 17 of the Industrial disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Khas Govindpur Colliery of Messrs Khas Govindpur Coal Company (Private) Limited, Post Office Katrasgarh, District Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st August, 1973.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

Reference No. 43 of 1971

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Parties :

Employers in relation to Khas-Govindpur Colliery of Messrs Khas Govindpur Coal Company (Private) Limited, Post Office Katrasgarh, District Dhanbad.

AND

Their Workmen.

Present :

Mr. Justice D. D. Seth (Retd.), Presiding Officer.

Appearances :

For the Bharat Coking Coal Ltd.—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

For the Employer—Shri D. Narsingh, Advocate.

For the Workmen—Shri J. D. Lall, Advocate.

State : Bihar. **Industry :** Coal.

Dhanbad, the 27th July, 1973

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-2012/130/71-LR. II, dated New Delhi, the 20th August, 1971 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :—

"Whether the action of the management of Khas Govindpur Colliery of Messrs. Khas Govindpur Coal Company (Private) Limited, Post Office Katrasgarh, District Dhanbad, in dismissing Shri Habib Mia, Tub Checker, from the 29th December, 1970 was justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The dispute has been settled by the parties out of Court. A Memorandum of settlement dated 27th July, 1973 has been filed today. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the Memorandum of Settlement. I accept it and make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

D. D. SETH, Presiding Officer.

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. I) AT DHANBAD

In the matter of:

Reference No. 43 of 1971

Parties:

Employers in relation to Khas-Govindpur Colliery

And

Their Workman

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

All the parties in the present proceedings have amicably settled the dispute involved in the present Reference on the terms hereinafter stated:

(1) That Shri Habib Mia, Tub Checker, the workman concerned in the present Reference shall be reinstated by the management of Khas-Govindpur Colliery on and from 30-7-1973 without any back-wages.

(2) That the period intervening from the date of dismissal (which gave rise to the present Reference) till the date of resumption of duty shall, for the purpose of continuity of services, be treated, as leave without pay, but the workman concerned will be eligible to proportionate leave or quarterly bonus provided he puts in proportionate qualifying attendance during the remaining period of current year or current quarter, as the case may be.

(3) In the event of the failure of the concerned workman to report for work within a fortnight from 30-7-1973 the workman concerned shall have no right for re-employment etc., under this agreement.

(4) That the above terms finally resolve the dispute between the parties and, therefore, there is no subsisting dispute for adjudication in the present Reference.

(5) That Shri J. D. Lall Advocate, the representative of the workman concerned will be paid Rs. 100 (Rupees One hundred only) towards the cost of proceedings.

For the Workman
J. D. LALL

For the Employer
Dharam Singh Advocate
for Manager Khas Govindpur Colliery.

For the Bharat Coking Coal Ltd.
Shri S. S. Mukherjee,

[No. L-2012/130/71-LRII.]

आदेश

का० आ० 2377—यतः यूनियन बैंक आफ इण्डिया से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व पंजाब नैशनल बैंक एम्पलाईज यूनियन, जलंधर करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और यतः उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के अनुसरण में माध्यस्थम् करार द्वारा विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त अधिनियम की धारा 10-क उपधारा (3) के अन्तर्गत उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उप-धारा (3) अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को, जो उसे 25 जुलाई, 1973 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1917 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम — **के बीच**

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री गुरशरण सिंह, कार्मिक अधिकारी, यूनियन बैंक आफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय (एन), नई दिल्ली ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री ओ० पी० सेहगल, महासचिव, पंजाब नेशनल बैंक एम्पलाईज यूनियन, (पी) जलंधर शहर ।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित विवाद को श्री डी० पंडा, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), कानपुर के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का एतद्द्वारा करार किया गया है :—

1. विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय:	"क्या श्री जी० के० बहल, विशेष सहायक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, जलंधर शहर का उनकी पदोन्नति के मामले में, अधिकारी ग्रेड 2 के रूप में अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां तो वह किस अनुतोष के हकदार हैं ?"
2 विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमे अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है ।	(1) यूनियन बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय (एन), नई दिल्ली । (2) वि पंजाब नैशनल बैंक एम्पलाईज यूनियन (पंजाब) (पंजीकृत), जलंधर शहर ।
3. यदि कर्मकार स्वयं विवाद में अन्तर्ग्रस्त हो, तो उसका नाम या यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मका या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम ।	वि पंजाब नेशनल बैंक एम्पलाईज यूनियन (पी०) पंजीकृत, जलन्धर शहर ।
4 प्रभावित उपक्रम मे नियोजित कर्मकारों की कुल सख्या ।	35 (पैंतीस)
5. विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या ।	1 (एक)

हम यह करार भी करते है कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्ध कर होगा। मध्यस्थ अपना पंचाट तीन मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पचाट् नही दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जायगा और हम नये माध्यस्थम् के लिये बातचीत करने को स्वतन्त्र होगे।

1. ह०/-गुरशरण सिंह
नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले
2. ह०/- ओ० पी० सहगल
महासचिव,
कर्मकार का प्रतिनिधित्व करने वाले।

साक्षी

1. ह०/-सत्यवान गुप्ता 6/7/73
2. ह०/-जे० सी० तुली ।

[फा० सख्या एल/12012/85/73-एल० आर०-3]
करनैल सिंह अवर सचिव

ORDER

S.O. 2377.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the Union Bank of India and their workmen represented by Punjab National Bank Employees Union, Jullundur;

And whereas the said employers and workmen have under sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the dispute to arbitration by arbitration agreement and have forwarded to the Central Government under sub-section (3) of section 10A of the said Act, a copy of the said arbitration agreement;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said arbitration agreeement which was received by it on the 25th July, 1973.

AGREEMENT

(Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Name of the parties:—	
Representing employers:	Shri Gursharan Singh, Personnel Officer, Union Bank of India, Regional Office (N), New Delhi.
Representing workmen:	Shri O. P. Sehgal, General Secretary, Punjab National Bank Employees Union, (P) Jullundur City.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri D. Panda, Regional Labour Commissioner (Central), Kanpur.

(i) Specific matters in dispute:—	"Whether Shri G.K. Bahl, Special Assistant, Union Bank of India, Jullundur City has been superseded in matter of his promotion as Officer Grade II? If so, to what relief is he entitled?"
(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved:	(1) Union Bank of India, Regional Office (N), New Delhi. (2) The Punjab National Bank Employees Union (Punjab) (Regd), Jullundur City.
(iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the Union, if any, representing the workman or workmen in question.	The Punjab National Bank Employees Union (P) Regd., Jullundur City.
(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected.	35 (Thirty five)
(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.	1 (One)

We further agree that the decision of the arbitrator shall be binding on us. The arbitrator shall make his award within a period of three months or within the such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case to award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

1. Sd/-Gursharan Singh
Representing Employer.
2. Sd/-O. P. Sehgal,
General Secretary,
Representing Workmen.

Witnesses:

1. Sd/-Satyawan Gupta
6/7/73
2. Sd/-J. C. Tuli.

[F. No. L-12012/85/73-LRIII]
KARNAIL SINGH, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1973

का० आ० 2378.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स चौगुल एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, की सिरीगाओ, माईन्स, मोर्मुगाओ हारबर (गोआ) से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (संख्या 2), मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स चौगुल एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड की सिरीगाओं माईन्स मोर्मुगाओ, हारबर (गोवा) के प्रबन्धतंत्र की, श्री एम० मुथुस्वामी, यूक्लिड ड्राइवर, सिरीगाओ माइन्स को उनके तारीख 15 जुलाई, 1971 के पत्र द्वारा पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित थी? यदि नहीं , तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

[संख्या एल-29012/18/73-एल० आर०-4]

ORDER

New Delhi, the 12th July, 1973

S.O. 2378.—WHEREAS the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Sirigao mines of Messrs Chowgule and Company Private Limited, Mormugao Harbour (Goa) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

AND WHEREAS the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Bombay, constituted under sections 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Sirigao mines of Messrs Chowgule and Company Private Limited, Mormugao Harbour (Goa) in dismissing Shri M. Muthuswami, Euclid Driver, Sirigao Mines, vide their letter dated the 15th July, 1971, was justified? If not, to what relief is the workman entitled?

[No. L-29012/18/73-LRIV]

आदेश

का० आ० 2379.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री मोती लाल मुंणी की बलवान सैंड स्टोन माईन इन्द्रगढ़ (कोटा) से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या श्री मोती लाल मुंशी, खान स्वामी की बलवान सैंडस्टोन माईन इन्द्रगढ़ (जिला कोटा) में नियोजित कर्मकारों की, लेखा वर्ष 1966-67, 1967-68, 1968-69 1969-70 और 1970-71 के लिए 20% की दर से बोनस के भुगतान की मांग न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार इनमें से प्रत्येक वर्ष के लिए बोनस की किस मात्रा के हकदार हैं?

[संख्या एल-29012/19/73-एल० आर०-4]

ORDER

S.O. 2379.—WHEREAS the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Balwan Sand Stone Mine of Shri Motilal Munshi, Indergarh (Kota) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

AND WHEREAS the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (a) of the sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the demand of the workmen employed in the Balwan Sand Stone Mine of Shri Motilal Munshi, Mine Owner, Indergarh (District Kota) for payment of bonus @ 20% for the accounting years 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70 and 1970-71 is justified? If not, to what quantum of bonus are the workmen entitled for each of these years?

[No. L-29012/19/73-LRIV]

आदेश

का० आ० 2380.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स के० पी० झुनझुनवाला, और जे०के० झुनझुनवाला द्वारा उड़ीसा इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड लाठकाटा, डाकघर राउरकेला जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) की भोलामल फायर क्ले माइन्स के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री लक्ष्मीधर मल्लिक होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स के० पी० झुनझुनवाला और जे० के० झुनझुनवाला, द्वारा उड़ीसा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, लाठकाटा, डाकघर राउरकेला, जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) की भोलामल फायर क्ले माइन्स के कर्मकारों की निम्नलिखित मांगें न्यायोचित हैं?

यदि हां तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?

(1) मालानुपाती काम के लिए वर्तमान मजदूरी दरों का वर्ष पुनरीक्षण।

(2) ले जाने और उठाने सम्बन्धी मजदूरी।"

[सं० एल-29011/37/73-एल० आर०-4]

ORDER

S.O. 2380.—WHEREAS the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to management of Bholamal Fire Clay Mines of Messrs K. P. Jhunjhunwala and J. K. Jhunjhunwala, C/o Orissa Industries Limited Lathkata Post Office Rourkela District Sundergarh (Orissa) and their workmen in respect of the matters specified in the schedule hereto annexed;

AND WHEREAS the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri Laxmidhar Mallick as presiding Officer with headquarters at Bhubaneswar and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the following demands of the Workmen of Bholamal Fire Clay Mines of Messrs K. P. Jhunjhunwala and J. K. Jhunjhunwala C/o Orissa Industries Limited Lathkata Post Office Rourkela, District Sundergarh (Orissa) are justified? If so, to what relief are the workmen entitled?

(i) Revision of existing wage rates for piecework.

(ii) Lead and Lift wages.

[No. L-29011/37/73-LR IV.]

आदेश

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1973

का. आ. 2381.—यतः भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2242, दिनांक 24 मई, 1971 द्वारा गठित गुंटूर स्थित श्रम-न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो गया है;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री डी. एल. एन. राजू को पूर्वोक्त गठित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[फा. संख्या एस-11011/11/73-एल. आर.-1]

एस. एस. सहरखानामन, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 1st August, 1973

S.O. 2381.—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the Labour Court with headquarters at Guntur, constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour & Employment) No. S.O. 2242 dated the 24th May, 1971.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri D. L. N. Raju as the Presiding Officer of the Labour Court constituted as aforesaid.

[F. No. S. 11011/11/73-LR. I.]
[No. 3/2/70-LR. I.]

New Delhi, the 8th August, 1973

S.O. 2382.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Hyderabad in the industrial dispute between the employers in relation to the Air Force Academy Project, Secunderabad and its workmen which was received by the Central Government on the 31st July, 1973.

[F. No. 3/2/70-LR. I.]

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD :

Present :

Sri T. Narsing Rao, M.A., LL.B., Industrial Tribunal (Central) Hyderabad.

Industrial Dispute No. 39 of 1971 :

BETWEEN

Workmen of Air Force Academy Project, Secunderabad.

AND

Management of Air Force Academy Project, Secunderabad.

Appearances :

Sri V. Jagannadha Rao, Advocate, for Workmen.

Sri K. Sripathy Rao, Advocate, for Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) through F. No. 3/2/70-LR.I dated 22-4-1971 referred the industrial dispute between the employers of Air Force Academy Project, Secunderabad and their Workmen, for adjudication by the Tribunal, under Section 10(1)(d) and Section 7A of the Industrial Disputes Act, 1947, on the following issues :—

"Whether the following demands of the workmen of the Air Force Academy Project, Dundigal, Secunderabad are justified and if so to what relief the workmen are entitled and from what date?

(i) Payment of Project Allowance to the staff, who are not regular but engaged on work of permanent nature.

(ii) Grant of continuity of service to workmen working in the project for long periods.

(iii) Leave facilities such as privilege leave, sick leave and casual leave.

(iv) Supply of Uniforms, shoes, soaps, goggles and caps for workers engaged in mixing cement and loading and unloading cement bags and those working on machines ?"

2. The workmen filed a claims statement alleging that though they were initially employed in the year 1967 or later as casual workmen, they have been performing the duties as regular workmen and that nature of the work performed by them continued beyond six months. Thus they were continued in employment beyond six months. But in order to deprive them from the benefits of the regular temporary employees, technical breaks in their continuity of service were effected after every 89th day and were again re-employed. They thus claim that they should be treated as regular workers from the date of the first appointment as casual workers. Their first claim is that Project Allowance which is admissible to regular employees should also be paid to them. Consequent to the claim for regularisation, the claim for leave facilities such as privilege leave, sick leave and casual leave is also put forward by them. The supply of uniforms etc., for the purposes of working on the project is also urged by them as essential for performing their duties. It is thus contended that in view of the continuity of the employment and also existence of a particular nature of work beyond six months they are entitled for regularisation from the date of their initial appointment as casual worker and also to the project allowance and other privileges like leave etc.

3. In the counter filed by the Management it was urged that the Academy Project is not an industry and therefore the provisions of Industrial Disputes Act have no application. It was contended that the term of employment of the casual employee gets terminated at the end of specific period. These workers are styled by the Management as casual employees, not entitled to the benefit of continuity of their service or the benefits under the Special Army Order. The claim for project allowance by these workmen on par with the regular temporary workmen is also denied on the ground that these workmen are only casual labourers. The benefit of leave etc. is also alleged not applicable to these workmen. The claim for supply of uniforms etc., (claim No. 4) is said to be dependent on the result of claims mentioned supra.

4. The Management sought the question of this establishment being not an industry tried as a preliminary issue. By an Order of this Tribunal dated 20th March, 1972 the Project is held to be an industry within the meaning of Section 2(j) of the Industrial Disputes Act. It is relevant to note that some of the workers who were served with notices of dismissal preferred Writ Petitions No. 3089 and 3090 of 1971 for writ of **mandamus** not to terminate the service of the petitioners during the pendency of this industrial disputes before this Tribunal. Those Writ Petitions were allowed, with costs Pending those two Writ Petitions, the workmen obtained Orders of stay on 20-8-1971 not to effect any break in their services. Writ Petition No. 2497/72 filed by the Management challenging the preliminary order of the Tribunal holding this establishment as an industry stood dismissed.

5. At the stage of enquiry the Management filed a memo of concessions to the following effect, seeking the disposal of this dispute in the light of the concessions ; "All the Casual Personnel employed in the Air Force Academy Project are to be brought on regular establishment from the date of the Orders of Stay in the Writ Petitions Nos. 3098 and 3090 of 71 (i.e.) 20-8-1971 subject to their furnishing written undertaking to the effect that they are prepared to serve in other defence installations elsewhere and produce Medical Fitness Certificates from authorised medical officers. As a result of the above, the personnel will be entitled for House Rent Allowance and City Compensatory Allowance, Continuity of Service, leave and other benefits. The opposite party submits that protective clothing will be provided only for certain categories of personnel who are eligible and which will be based on the recommendations of the Inspector of Factories." No oral evidence is led by either party. On behalf of the Workmen Ex. W1 a copy of the letter of Government of India. Ministry of Defence, dated 10th September, 1953 relating the conditions of service of workmen employed in Casual capacity,was marked by consent.

6. In view of the Memo of concessions filed by the Management, the claim of the Workmen for being regularised stands conceded, though the date of regularisation is a matter of controversy. It is also conceded in the said Memo that once a casual worker is regularised, he will be entitled for House Rent Allowance, City Compensatory Allowance, Continuity in Service, Leave and other benefits. It is also conceded that the protective clothing (claim No. 4) will be provided for certain categories of personnel who are eligible and to whom such clothing will be recommended by the Inspector of Factories. The Memo however lays down two more

conditions that the regularised employees should give written undertaking to the effect that they would serve in other Defence Installations elsewhere and also produce Medical Fitness Certificates from authorised Medical Officers. Mr. Jagannadha Rao, learned counsel for the Workmen conceded that the workmen have to produce the Medical Fitness Certificate. He however disputes the need or the desirability of the insistance upon an undertaking by a workman to serve in Defence Installations throughout India or anywhere else, once the Casual Labour is regularised. It can however be noted that once an employee is regularised in this Project which is an undertaking of Government of India, it automatically follows that the Management has the right to transfer the Worker to any other Defence Installations in any part of the Country. Thus the conditions sought to be imposed for the purpose of regularisation need no more detain the further and the more important question as to the date of regularisation.

7. The contention of the learned counsel for the Workmen was that though the workmen were initially appointed as Casual labour, and the work continued beyond six months temporary breaks were given on every 89th day but the same workmen were re-employed on the second or the third day and on the same job. It is thus urged that the service of the workmen was continuous and the particular type of work also continued. Having regard to the circumstances it was urged that the workmen would fall within the definition of permanent workmen and it is not necessary that the work should last throughout the year. This submission was made in view of so called temporary breaks. The learned counsel for the workmen is well supported by an authority, reported in JASWANT SUGAR MILLS LTD. v. BADRI PRASHAD (Labour Judgements, Volume 5, 1950-67 (Supreme Court) Page 3474). Rellance is also placed by him on another ruling reported in N. J. CHAVAN v. P. D. SAWARKAR (AIR 1958 Bombay, page 133). It is held therein "By continuity of service is not meant necessary legal continuity but only continuity in fact; that is the employees must continue to serve the business without a substantial break in service." I need not dwell at length on this aspect of the case, since the Management concedes that these workmen initially employed as Casual labouress are entitled to have their service regularised.

8. The question therefore is what is the date from which the workmen are entitled to be regularised. In this context the workmen relied upon the Clause 5 of Ex. W1 which reads as follows : "If for any reason the apointment is to continue beyond six months, the individual will not be discharged and re-employed from the same date. Instead he will be allowed to continue in service without any break and will be treated as a regular industrial employee from the date of his original appointment as casual industrial employee. This change of category from Casual to Regular will be declared even before the expiry of six months as soon as it is definitely known that the individual will continue in service beyond six months. "The contention of the counsel for the Workmen therefore is for regularisation of the services from the date of their original appointment as casual employee. The Management has put forward the date of regularisation as from 20th August, 1971 the day on which the High Court in the Writ Petitions granted Stay Orders not to effect break in the service of the workmen. A few other dates are relevant in this context. The workmen served a strike notice on the Chief Engineer, Air Force Academy Project on 26th March, 1970. This was in continuation of a charter of demands presented to the Chief Engineer, Air Force Academy Project on 12-3-1970. The reference as noted above is made by the Government of India on 22nd April, 1971. The contention of the learned Counsel for the workmen is that even in the light of Ex. W1 their services are to be regularised from the date of their first appointment as Casual labourers. It is common case that the monetary benefits and other incidental benefits like Leave etc., would follow the date of regularisation. The date as suggested by the Management though not un-reasonable appears to be arbitratory. Any award passed by the Tribunal with reference to the matters in issue would be operative from the date of the enforceability i.e. after one month of the publication of the award under Section 17A of the Industrial Disputes Act. But under Section 17 of the said act it is equally open to the Tribunal to fix any other date as the date of the operation of the award. Thus the date of regularisation as claimed by the workmen and also the date as suggested by the Management in the above memo, would have the effect of giving a retrospective effect to the award.

9. The short point that falls for consideration is as to what should be the date of regularisation. It is relevant to note that the reference by itself does not pose the question as to the specific date from which the services are to be regularised. It is however open to an Industrial Tribunal even without a specific reference on the question as to when an award should become operative to fix a date from which it shall come into operation. It is held in HINDUSTAN TIMES LTD., v. THEIR WORKMEN (AIR 1963 Supreme Court at page 1332). "Even without a specific reference being made on the question as to when an award comes into operation it is open to an Industrial Tribunal to fix in its discretion a date from which it shall come into operation. No general formula can be laid down as to the date from which a Tribunal should make its award effective. That question has to be decided by the Tribunal on a consideration of circumstances of each case. Indeed, it is difficult and not even desirable that the Supreme Court should try to lay down general principles on such matters that require careful consideration of the peculiar circumstances of each case for the exercise of discretion." The consideration that should weigh with Tribunal while giving retrospective effect are well laid in a ruling of the Supreme Court reported in INDER SINGH AND SONS v. THEIR WORKMEN (1961 (II) FLR, page 583). It is held therein "On the question whether retrospective effect can be given to an award in industrial adjudication, no doubt laws of limitation which might bar any Civil Court from giving remedy in respect of lawful rights should not be applied by Industrial Tribunals, but over-stale claims should not generally be encouraged or allowed unless there is satisfactory explanation for the delay. Both the risk to industrial peace from the entertainment of claims after a long lapse of time and the unsettling effect this is likely to have on the employer's financial arrangements should be taken into account. Whether a claim has become too stale or not will depend on the facts of each case.

In deciding the date from which relief should be given, the Industrial Tribunal ought to pay particular attention to the date when the demand was first made though it cannot be said that relief can in no case be granted for a period prior to the demand." The strenuous contention of the learned counsel for the Workmen was that no amount of lapses on their part would disentitle them for being regularised from the date of their first employment. In the list of the typical cases of workmen who are entitled for regularisation, filed along with the claim statement, the names of workmen employed in 1967 are also shown. If they are deprived of the Project Allowance since then which was being paid to the other regular workmen there is no reason as to why they could not have put forward their claim till March, 1970. It is true that the demand cannot said to be a over-stale demand nor the law of limitation can be held applicable to these demands. It is equally true that the Management in breach of its own circular (Ex. W1) has been effecting technical breaks in the services of the workmen, thereby it deprived the workmen of the benefits to which they were otherwise entitled. Thus both the parties were in fault. The other consideration and a necessary consideration as laid down by the above ruling is the un-settling effect that is likely to have on the employers financial arrangement. It is true that the Project is a Government undertaking but that does not make the position of the employer in any way different. Though it cannot be said that there was inordinate lapse of time in putting forward the demand, the delay, whatever it is, cannot be ignored. Having regard to the above tests I hold that even the date of the reference (22-4-1971) or the subsequent date (20-8-1971) as suggested by the Management would adversely effect the interests of the workmen. On a fair appraisel of the facts and paying particular attention to the date when the demand was first made I hold that the Workmen-Petitioners are entitled to be regularised from 12th March, 1970. In the light of the above discussion I answer the reference in the following terms :—

(1) The Workmen are entitled for regularisation and continuity of their services from 12th March, 1970 (issue No. 2).

(2) They are entitled to the payment of Project Allowance, Leave facilities, such as Privilege Leave, Sick Leave and Casual Leave from 12th March, 1970 (issue Nos. 1 and 3)

(3) The Management as per its undertaking should hereafter supply uniforms, shoes, soaps, goggles and caps to such of the workmen as recommended by the Chief Inspector of Factories (issue No. 4)

(4) The workmen have to produce Medical Fitness Certificate for the purpose of their regularisation. Further in view of their regularisation the workmen shall be bound to serve in any other Defence Installations throughout India.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this 18th day of July, 1973.

Signature illegible
T. NARSING RAO,
Industrial Tribunal.

APPENDIX OF EVIDENCE :

Witnesses examined for Workmen.	Witness examined for Employers.
NIL.	NIL.
Documents exhibited for Workmen.	Documents exhibited for Employers.
	NIL.

Ex. W1 : Copy of the letter No. 2 (17)51/10805/D (CIV) dt. 10-9-53 of Government of India, Ministry of Defence.

Signature illegible,
T. NARSING RAO,
Industrial Tribunal.

[File. No. 3/2/70-LR. I]

New Delhi, the 8th August, 1973

S.O. 2383.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Iron Ore Mines of Messrs G. N. Agarwal, Post Box 107, Margo (Goa) and their workmen, which was received by the Central Government on the 31st July, 1973.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, BOMBAY

Reference No. CGIT-27 of 1967

Parties :

The management of the Iron Ore Mines, of M/s. G. N. Agrawal, Margoa, Goa.

AND

Their Workmen.

Present :

Shri A. T. Zambre, Presiding Officer.

Appearances :

For the employers—Shri G. M. Kothari, Advocate.

For the workmen—Shri George Vaz, General Secretary, Goa Mining Labour Welfare Union.

State : Union Territory of Goa. **Industry :** Mining (Iron Ore).

Bombay, dated 29th June, 1973

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, Department of Labour and Employment have by their Order No. 24/32/67-LRI have referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of the iron ore mines of M/s. G. N. Agrawal Post Box 107, Margoa (Goa) and their workmen in respect of the matters specified in the following schedule :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Iron Ore mines of M/s. G. N. Agrawal, Post Box 107, Margao (Goa) in retrenching the following workmen with effect from the 22nd September, 1967 was justified ?"

	Name	Designation	Iron Ore Mine
1.	N. F. Gonsalves	Clerk	BIMAL MINE
2.	S. V. Aramani	Clerk	" "
3.	A. S. P. Desai	Clerk	" "
4.	Vaukunt Kelkar	Supervisor	" "
5.	A. K. Coitinho	Supervisor	" "
6.	A. P. Masquita	Supervisor	" "
7.	Chandrakant Usgoancar	Supervisor	" "
8.	Uttam Rama Naik	Supervisor	" "
9.	I. M. Pereira	Supervisor	" "
10.	Robin Rodrirgues	Supervisor	" "
11.	Mohamed Akbar Najung	Fitter/Operator T. D. No.	" "
12.	Datta Naik	Cleaner	" "
13.	Mathew Dennis	Cleaner	" "
14.	Vitol Prob	Cleaner	" "
15.	Gopal Bagule	Cleaner	" "
16.	Rajaram Khandeparkar	Cleaner	" "
17.	Jeronio D'Mello	Cleaner	" "
18.	John Vaz	Cloaner	" "
19.	Isidorio Dias	Com. Driver	" "
20.	R. Motiram	Com. Driver	" "
21.	Francis Moneiora	Com. Driver	" "
22.	Vijay Morcolcar	Cook	" "
23.	Cruz Fernandes	Clerk	COLOMBA MINE
24.	Edgar Rebello	Clerk	MAINA MINE
25.	Prabarkar Raikar	Clerk	" "
26.	Felix Pais	H. Supervisor.	COLOMBA MINE
27.	Prabhakar Gad	Supervisor	MAINA MINE
28.	Isoderio Fernandes	Supervisor	" "
29.	Lawrence Fernandes	Blaster	" "
30.	Mohan Bastawarcar	Shovel Operator	" "
31.	M. Louis	In-Charge	COLOMBA MINE
32.	A. L. Manjrakar	Asstt. In-Charge	" "
33.	V. V. Kashalcar	Supervisor	BIMAL MINE
34.	Attakin Radakrishna	Com. Driver	MAINA MINE
35.	Gurudas Manjrecar	Com. Driver	" "
36.	Babuli Dabolcar	Driller	" "
37.	Concessao Fernandes	Chief Shovel OPE. Michigan	" "
38.	Chandrakant Dargalcar	Asstt. Shovel Ope	" "

If not, to what relief are the workmen entitled?".

2. The employers M/s. G. N. Agrawal, Post Box No. 107, Goa, are a Hindu undivided family firm carrying on the industry of mining of iron ore. They have three mines one at Bimol the second at Colomba and third at Maina in the union territory of Goa. The company has been extracting iron ore for the purpose of export to Japan and other foreign buyers and had a large number of employees in their employment. They have by a notice dated 22-8-1967 retrenched a large number of

workers on the rolls of their concern. The employees were the members of the Goa Mining Labour Welfare Union affiliated to the AITUC and hence the union raised a dispute by a letter dated 28-8-1967 and submitted a charter of demands before the Assistant Labour Commissioner (Central) Vasco-da-Gama. They also served a strike notice and the Assistant Labour Commissioner entered the dispute in concillation and issued notices. The management also was represented by their representatives but as the conciliation ended in failure the Assistant Labour Commissioner submitted a failure report on which the Central Government referred this dispute for adjudication.

3. The Goa Mining Labour Welfare Union has by their statement of claim contended that the employers had in their employment about 800 workmen including piece-rates workers. They carry on the business of extracting iron ore and exporting. The company is one of the major mining concerns in Goa and is a member of the Goa Mineral Ore Exporters Association. The company has at its disposal the latest and modern mining equipment and uptodate machinery engaged in the industry for extracting iron ore and the mining industry was expanding by leaps and bounds in the region of Goa. The industry is prospering tremendously and there was absolutely no justification for the retrenchment. The union has contended that the notices of retrenchment were illegal, invalid, unjust, mala fide and were issued with ulterior motives. They have contended that the allegations of the company that the management had taken the decision to stop mining activities as they were found to be uneconomical were false, fabricated and mala fide and the retrenchment was brought about with ulterior motives with an intention to defeat the claims of the workmen and deny to them the benefits accruing under the recommendations of the Wage Board constituted by the Government of India. They have further contended that the notices of retrenchment were not in the prescribed form. The company had not also given retrenchment compensation to the workmen. The Company was bount to maintain a list of seniority and was further bount to display the same for the benefit of the workmen but no such notices were displayed. The retrenchment was not also brought about on the principle of statutory provisions of 'last come first go and the retrenchment was unfair and improper and the workmen should be reinstated and they should be paid adequate compensation for their loss of earnings during the period of unemployment.

4. The employers have by their written statement opposed the reference on the technical grounds that the reference had not been made by the appropriate Government. The appropriate Govt. in this case is the Union Territory of Goa—that is the Administrator and hence the reference was invalid and the Tribunal has no jurisdiction. Regarding the merits they have contended that the employers M/s. G. N. Agrawal was a Hindu undivided concern and in the year 1966 the joint Hindu family concern was partially partitioned as a result of which the joint Hindu family properties excluding the mines became the property of members; such as Shri G. N. Agrawal Mrs. Naintara Agrawal and Shri Krishnakumar Agrawal. Because of certain impediments the mines however stood under the name and style of M/s. G. N. Agrawal (H.U.F.) and continued to belong to the joint Hindu family. But the machinery and equipments were divided in the partial partition and the machinery and equipment ceased to the property of the joint Hindu family. The employers M/s. G. N. Agrawal lost the ownership and control over the machinery as the machinery went to the shares of different members. Under the circumstances M/s. G. N. Agrawal, Hindu undivided Family had no alternative left but to adopt rationalisation measures such as retrenchment.

5. The machinery had gone to the shares of different member of the joint family and a new company M/s. G. N. Agarwal Minerals (Goa) Pvt. Ltd., had acquired the machinery from these different members, M/s. G. N. Agrawal (H.U.F.) entered into an arrangement with M/s. Agrawal Minerals (Goa) Pvt. Ltd., for exploration and carrying on the mining operations, and the letter is engaged in mining exploration. As a result of the dissolution of the joint Hindu Family and consequential partition which was inevitable the whole business of M/s. G. N. Agarwal had to undergo perforce various changes and one of the results was the retrenchment under consideration. It is contended that with effect from 18th December 1966 the employers had entered into a contract with M/s. Agarwal Minerals (Goa) Pvt. Ltd., a company duly incorporated and registered under the Indian Companies Act for extraction of iron ore from the mines at Bimbal and the other two mines at Maina and Columbia were given to them on royalty basis. They have further contended that the financial condition of the employer was not good and the running of the unit had become uneconomical with the result that the extraction of iron ore had become an uneconomic proposition and the exports could not stand in the competitive international market and under the circumstances the employers had to effect retrenchment and the same was justified.

6. The reference was further resisted on the contention that out of the 38 workers who were retrenched by the employer 29 workers had already accepted the retrenchment compensation and all other dues in full and final settlement of all their claims and as such no dispute remained or survived in respect of those 29 workers and the remaining did not constitute a substantial number of workmen to sufficiently espouse the cause of all the workmen and in the circumstances no industrial dispute could be said to have arisen. It has been contended that the workmen have been offered the necessary and all legal dues and the employer has fulfilled all the statutory requirements for effecting retrenchment and the same is valid and lawful and the retrenchment was justified.

7. The dispute was required to be adjourned on many occasions as the parties wanted to negotiate but they could not come to terms. At first the preliminary issue about jurisdiction was heard and I have by my order dated 3rd March, 1971 held that the Govt. of India had in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act passed the reference order and though in the rules it was stated that the reference to Central Govt. or Government of India in respect of a union territory should be construed as a reference to the Administrator of the Territory as the reference order was passed under section 10 of the Act and not under the rules the Central Government has the necessary powers and the reference was valid.

8. After the finding about jurisdiction the reference was kept for hearing but the same was required to be adjourned as the parties wanted to negotiate the dispute and ultimately when the matter was fixed for hearing at Panjim on 28th June 1973 the parties filed a joint memorandum of settlement. According to the terms the parties have agreed that all the workmen expect two viz., Felix Pais and John Vaz had accepted their dues including retrenchment compensation in full and final settlement directly from the employers and were not interested in pressing the present reference. As regards the remaining two workmen the management has agreed to pay them in full and final settlement Rs. 950 and Rs. 450 respectively and both parties have agreed that there was no further claim or demand subsisting in respect of the retrenchment and the whole dispute covered by the reference stood settled. Both parties submitted that the settlement was just and fair and in the interests of the workmen and an award should be passed in terms of the same.

9. The employers had their written statement itself contended that out of the 39 workmen 29 had already accepted their retrenchment compensation and all other dues in full and final settlement of all their dues and claims. Shri Cruz Fernands, A. L. Manjrekar and Conceisao Fernandes tendered their resignations, one workman Shri V. V. Kushalkar had secured permanent employment with some other employer and was not interested in the reference and six persons out of the remaining retrenched persons had been already employed by M/s. Agarwal Minerals (Goa) Pvt. Ltd., thus it is clear that a large number of workmen involved in the reference had already settled their claims directly with the employers.

10. Regarding merits the management had produced a copy of the award between the same parties in respect of the retrenchment of the workmen at the workshop of the joint hinda family. In that reference the union had raised the same issues as in the present reference and after hearing the parties in that reference viz., Ref. No. IT-GDD No. 7 of 1967 the tribunal had passed a award upholding the partition and the employers have contended that the issue was barred by res-judicata. From the previous award it is clear that the Tribunal had accepted the plea of partition raised

by the employers and in view of the circumstances it shall have to be held that the terms of settlement are fair and reasonable and in the interests of the workmen. Out of the 38 workmen all except two have accepted the compensation in full and final settlement of their claim. The remaining two workers have also now accepted the amounts in full and final settlement of the claim and as the terms of settlement are reasonable I pass an award in terms of the settlement exhibit 'A' which shall form part of this award.

No order as to costs.

A. T. ZAMBRE, Presiding Officer.

BEFORE SHRI A. T. ZAMBRE, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL

C.G.I.T. Ref. 27 of 1967

BETWEEN

Employer in relation to the management of Iron Ore Mines of M/s. G. N. Agrawal, Margao

AND

Their Workmen

In the matter of Retrenchment

May it please the Hon'ble Tribunal

1. The parties have settled the reference as follows :—

(a) That all the workmen except Felix Pais and Jhon Vaz have accepted all their dues including retrenchment compensation in full and final settlement directly from the employers and are not interested in pressing the present reference. Hence, retrenchment in all such cases is justified. Gurudas Manjrekar's services were terminated earlier to retrenchment and he accepted his dues.

(b) That the employers agree to pay to the remaining two workmen Mr. Felix Pais and Jhon Vaz the following amounts in full and final settlement of all their dues including retrenchment etc. and claims :—

FELIX PAIS : Rs. 306 (Retrenchment compensation) plus Rs. 644 ex-gratia total Rs. 950.

JOHN VAZ : Rs. 228/22 (Retrenchment and other dues) plus Rs. 221/78 ex-gratia total Rs. 450.

These amounts of Rs. 950 and Rs. 450 will be paid to them within a month hereof.

(c) That there are no further claims or demands now subsisting in respect of retrenchment and the whole dispute covered by the present reference stands settled as above.

2. That the above settlement is just and fair and in the interest of the workmen. Hence it is prayed that the Hon'ble Tribunal may be pleased to pass an award in terms of the above.

for GANGADHAR NARSINGDAS AGRAWAL
(Sd.) ILLEGIBLE
Constituted Attorney
(Sd.) ILLEGIBLE
Advocate for Employers
GEORGE VAZ, Gen. Secy.
Goa Mining Labour Welfare Union, Bardez, Goa.

Panjim, Goa.
28th June, 1973.

[No. 24/32/67. LR. I/LR. IV]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1973

का. आ. 2384—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कलकत्ता चिप्पिंग, पेंटिंग तथा जहाज श्रम ठेकेदारों के ऐसोसिएशन, कलकत्ता से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और, यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

1. "क्या गैर पंजीकृत चिप्पिंग और पेंटिंग श्रमिकों, अर्थात् नैमित्तिक पर्यवेक्षकों, फोरमैनों, गेयरमैनों तथा क्लीनिंग मैनों की पत्तन तथा गोदी उद्योग संबंधी मजदूरी बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों से मासिक आधार पर मकान किराये और नगर प्रतिकर भत्ते के भुगतान की मांग न्यायोचित है और यदि, हां, तो किन शर्तों पर और किस तारीख से ।"

2. "क्या पर्यवेक्षकों तथा फोरमैनों के सम्बन्ध में 75 रु. प्रति मास तथा गेयरमैनों व क्लीनिंग मैनों के सम्बन्ध में 60 रु. प्रति माह की दर से निर्वाह भत्ते के भुगतान की मांग न्यायोचित है और यदि हां तो किन शर्तों पर और किस तारीख से ।"

[सं. एस-32011/12/73-पी. एण्ड डी. (1)]

ORDER

New Delhi, the 3rd August, 1973

S.O. 2384.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Calcutta Chipping, Printing & Ship's Labour Contractors' Association, Calcutta and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed :

And whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

1. "Whether the demand of the un-Registered Chipping and Painting workers namely casual supervisors, Foremen, Gearmen and Cleaningmen for payment of House Rent and City compensatory allowance at the rates prescribed by the Wage Board for Port & Dock Industry on a monthly basis is justified and if so, under what conditions and from what date".

2. "Whether the demand for payment of subsistence allowance at the rate of Rs. 75/- per month in respect of Supervisors and Foremen and @ Rs. 60/- per month in respect of Gearmen and Cleaningmen is justified and if so under what conditions and from what date".

[No. L-32011/12/73-P&D(I)]

आदेश

का० आ० 2385— यतः भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, (श्रम और रोजगार विभाग) के आदेश संख्या एस-32011/12/73-पी० एण्ड डी० (i) तारीख 3 अगस्त, 1973 द्वारा कलकत्ता चिप्पिंग, पेंटिंग एंड शिप कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन, कलकत्ता और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद न्याय निर्णयन के लिए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को निर्दिष्ट किया गया है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद के संबंध में विद्यमान हड़ताल के चलते रहने का प्रतिषेध करती है।

[सं० एल-32011/12/73-पी०एण्ड डी० (2)]

ORDER

S.O. 2385.—Whereas, by the order of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. L-32011/12/73-P&D(i), dated the 3rd August, 1973 an industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Shipping, Painting & Ship's Labour Contractors' Association, Calcutta and their workmen has been referred to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby prohibits the continuance of strike in existence in connection with the said dispute.

[No. L-32011/12/73-P&D(ii)]

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1973

का० आ० 2386.— यतः मैसर्स तुलसीदास खिमजी प्राइवेट लिमिटेड, वीर नारीमन रोड, बम्बई-1 के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व परिवहन तथा गोदी श्रमिक यूनियन, बम्बई करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को, जो उसे 19 जुलाई, 1973 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।

औद्योगिक अधिनियम, 1947 की धारा 10क के अधीन करार के बीच

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री शान्तु करसनदास, मैसर्स तुलसीदास खिमजी प्राइवेट लि०, वीर नारीमन रोड, बम्बई-1 के विधि सम्मत मुख्तार-1

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री एम० आर० कुलकर्णी, परिवहन तथा गोदी श्रमिक यूनियन, पी० डि'मेल्लो रोड, बम्बई-1।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को एतद्द्वारा श्री एम० आर० मेहेर, आई० सी० सेवा-निवृत्त आदर्श नगर, वर्ली, बम्बई-25 और श्री एल० पी० वावे, आनन्द पार्क सोसाइटी, ब्लाक-1/2, नादियाद (गुजरात) के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

(1) विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय — मैसर्स तुलसीदास खिमजी प्राइवेट लि० के कर्मकारों को प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीने की कुल मजदूरी के प्रचलित रिवाजी बोनस के अतिरिक्त, वर्ष 1968/69, 1969/70, 1970/71, वर्षों के संबंध में देय बोनस की प्रमात्रा क्या होनी चाहिए।

(2) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्वलित स्थापन का नाम और पता भी सम्मिलित है: — मैसर्स तुलसीदास खिमजी प्राइवेट लि०, क्लेयरिंग और फार्वर्डिंग एजेण्ट, जिनका कार्यालय, वीर नारीमन रोड, बम्बई-1 में है।

(3) यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उस का नाम — परिवहन तथा गोदी श्रमिक यूनियन, पी० डि'मेल्लो रोड, बम्बई-1 जो मैसर्स, तुलसीदास खिमजी प्राइवेट लि०, के कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करती है।

(4) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या : 159

(5) विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या : 159

हम यह करार भी करते हैं कि यदि मध्यस्थों की रायें समानरूप से अलग-अलग होंगी तो वे एक अन्य व्यक्ति को पंच नियुक्त करेंगे, जिसका पंचाट हम पर आबद्धकर होगा।

मध्यस्थ अपना पंचाट माध्यस्थम् की कार्रवाई प्रारंभ होने की तारीख से चार मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देंगे। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जायगा और हम नये माध्यस्थम् के लिये बातचीत करने को स्वतन्त्र होंगे।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

ह०/-शांतु करसनदास,
मैसर्स तुलसीदास
विधि सम्मत मुख्तार
मैसर्स खिमजी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से।

ह०/-एम० आर० कुलकर्णी,
सचिव,
परिवहन और गोदी श्रमिक यूनियन की ओर से।

साक्षी :

1. ह०/-एम० बी० भट,
2. ह०/-आई० एस० सावन्त

[संख्या एल-31013/3/73-पी० एण्ड डी०]

ORDER

New Delhi the 6th, August, 1973

S. O. 2386.—Whereas an industrial dispute exits between the employers in relation to the management of Messrs Tulsidas Khimji Private Limited, Veer Nariman Road, Bombay-1 and their workmen as represented by the Transport and Dock workers Union Bombay;

And, whereas the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government under sub-section (3) of section 10A of the said Act, a copy of the said, arbitration agreement;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement, which was received by it on the 19th July, 1973.

AGREEMENT UNDER SECTION 10A OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT. 1947

BETWEEN

Representing employers: Shri Shantu Karsandas, Constituted Attorney of Messrs Tulsidas Khimji Private Limited, Veer Nariman Road, Bombay-1.

Representing workmen: Shri S.R. Kulkarni, Transport and Dock Worker's Union, P.D Mello Road, Bombay-1.

It is hereby agreed between the parties to refer the following industrial dispute to the arbitration of :—

Shri M.R. Meher, I.C.S., Retired, Adarsh Nagar, Worli, Bombay-25.

AND

Shri L. P. Dave, Anand Part Society, Block—1/2, Nadiad (Gujarat).

(i) Specific matters in dispute:—

"What should be the quantum of bonus that is payable to the workmen of Messrs Tulsidas Khimji Private Limited in respect of the years 1968-69, 1969-70, 1970-71 and 1971-72 in addition to the usual and customary bonus of one month's total wages for each year ?"

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved:

Messrs Tulsidas Khimji Private Limited, Clearing and Forwarding Agents, having its office at Veer Nariman Road Bombay-1.

(iii) Name of the union, if any, representing the workmen in question:

Transport and Dock Workers' Union, P.D. Mello Road, Bombay-1, representing workmen of Messrs Tulsidas Khimji Private Limited.

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected:

159

(V) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute:

159

We further agree that in case the arbitrators are equally divided in their opinion, they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us.

The arbitrator shall make their award within a period of four months from the date on which arbitration proceedings would commence, or within such further time as extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforesaid, the refereence to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate a fresh arbitration.

Signature of the parties:

Sd/-SHANTU KARANDAS,
Constituted Attorney
for Messrs Tulsidas Khimji Pvt. Ltd.

Sd/-S.R. KULKARNI,
Secretary
for Transport and Dock Workers Union.

Witness: 1. Sd/-M.B. Bhatt.
2. Sd/-I.S. Sawant.

[No. L-31013/3/73-P&D]

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1973

का० आ० 2387.—विशाखापत्तनम डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त उपधारा द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है, प्रकाशित किया जाता है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप के बारे में जो आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त होंगे, उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप स्कीम

1. इस स्कीम का नाम विशाखापत्तनम डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1973 है।

2. विशाखापत्तनम डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में,—

(क) खण्ड 15 के उपखण्ड (2) में,—

(i) मद (क) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) फोरमैन 'ए' और 'बी'।"

(ii) मद (ग) और (घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) विन्चड्राइवर।

(घ) सिगनलर-एवम्—टिप्पर।";

(ख) खण्ड 29 में, "विन्चमैन और सिगनलमैन-एवम्—टिप्पर" शब्दों के स्थान पर "विन्च ड्राइवर और सिगनलर एवम् टिप्पर" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खण्ड 41 में,

(i) शीर्षक में आने वाले "विन्चमैन, टिप्पर" शब्दों के स्थान पर "विन्चड्राइवर, सिग्नलर-एवम्—टिप्पर" शब्द रखे जाएंगे,

(ii) विन्चमैन, टिप्पर के प्रवर्ग शब्दों के स्थान पर "विन्चड्राइवर, सिग्नलर एवम् टिप्पर" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) अनुसूची 1 में, खण्ड (2) में,—

(i) मद (क) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) फोरमैन 'ए' और 'बी' ";

(ii) मद (ग) और (घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) विन्चड्राइवर।

(घ) सिग्नलर-एवम्—टिप्पर।"

[फा० सं० डी—15013/5/72-पी एण्ड डी]

New Delhi, the 8th August, 1973

S.O. 2387.—The following draft of a Scheme further to amend the Vishakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry

of a period two months from the date of publication of this notification in Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Scheme

1. This Scheme may be called the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1973.

2. In the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959,—

(a) in sub-clause (2) of clause 15,—

(i) for item (a) and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"(a) Foreman 'A' and 'B'." ;

(ii) for items (c) and (d) and the entries relating thereto, the following shall respectively be substituted, namely :—

"(c) Winchdriver.

(d) Signaller-cum-Tipper." ;

(b) in clause 29, for the words 'Winchman and Signalman-cum-Tipper', the words "Winchdriver and Signaller-cum-Tipper" shall be substituted ;

(c) in clause 41,—

(i) for the words "Winchman, Tipper", occurring in the heading, the words "Winchdrivers, Signaller-cum-Tipper" shall be substituted ;

(ii) for the words "categories of Winchman, Tipper", the words "Categories of Winchdriver, Signaller-cum-Tipper" shall be substituted ;

(d) in Schedule I, in clause (2),—

(i) for item (a) and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(a) Foreman 'A' and 'B'

(ii) for items (c) and (d) and the entries relating thereto, the following shall respectively be substituted, namely :—

"(c) Winchdriver.

(d) Signaller-cum-Tipper."

[No. V. 15013/5/72-P&D]

का० आ० 2388—विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 19) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त उपधारा द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप के बारे में जो आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के अवसान के पूर्व प्राप्त हों, उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप स्कीम

1 इस स्कीम का नाम विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1973 है।

2 विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 में,—

(i) खण्ड 17 के उपखण्ड (2) में,—

(क) "प्रवर्ग 'ख'" शीर्षक के अन्तर्गत, मद 5 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "गनि/मिलान-क्लर्क" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(ख) "प्रवर्ग 'ग'" शीर्षक के अन्तर्गत मद 7 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "गनि/मिलान क्लर्क" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(ii) अनुसूची में,—

(क) "प्रवर्ग 'ख'" शीर्षक के अन्तर्गत, मद 5 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "गनि/मिलान क्लर्क" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ख) "प्रवर्ग 'ग'" शीर्षक के अन्तर्गत, मद 7 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "गनि/मिलान क्लर्क" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा० सं० V 15013/5/72-पी एण्ड डी]

वी० शंकरालिंगम, अवर सचिव

S.O. 2388.—The following draft of a Scheme further to amend the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Scheme

1. This Scheme may be called the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1973.

2. In the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968,—

(i) in sub-clause (2) of clause 17,—

(a) under the heading "Category 'B'," for the entry against item 5, the entry "Gunny/Tally Clerks" shall be substituted ;

(b) under the heading "Category 'C'", for the entry against item 7, the entry "Gunny/Tally Clerks" shall be substituted ;

(ii) in the Schedule,—

(a) under the heading "Category 'B'", for the entry against item 5, the entry "Gunny/Tally Clerks" shall be substituted.

(b) under the heading "Category 'C'", for the entry against item 7, the entry "Gunny/Tally Clerks" shall be substituted.

[No. V. 15013/5/72-P&D]

V. SANKRALINGAM, Under Secy.

का० ग्रा० 2389.—यतः कृषि के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा यथापेक्षित, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० ग्रा० 3221, तारीख 25 अगस्त, 1972 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 28 अक्टूबर, 1972 के पृष्ठ 4693-4698 पर उन सभी व्यक्तियों की, जिनका उनसे प्रभावित होना संभाव्य था, जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे और जिसमें उनसे उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप, सुझाव या अभ्यावेदन मांगे गए थे;

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 28 अक्टूबर, 1972 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और यतः उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त हुए सभी आक्षेपों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विषय पर जारी की गई सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरें, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 1 की तत्संबंधी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट कृषि के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय हैं, पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कर्मचारियों के प्रवर्ग	सब मिलाकर प्रति दिन मजदूरी की न्यूनतम दरें				
	क्षेत्र ए रु० पै०	क्षेत्र बी-1 रु० पै०	क्षेत्र बी-2 रु० पै०	क्षेत्र सी रु० पै०	क्षेत्र डी रु० पै०
1	2				
अकुशल :					
(1) बेलदार (पुरुष/स्त्री); (2) काफ बाय; (3) पशुपाल; (4) चौकीदार; (5) क्लीनर, (6) क्लीनर (मोटर, भेड़, ट्रैक्टर, पशुशाला, एम० टी०); (7) खुला चारा एकत्रित करना; (8) धोबी; (9) डेरी कुली; (10) डेरी वाला; (11) स्टाक खोलना; (12) ड्रैसर; (13) ड्राइवर; (बैल, खच्चर); (14) फीडर (वयस्क) सूखी घास; (15) घास काटने वाला; (16) चरवाहा; (17) मददगार (भण्डार-मजदूर); (18) श्रमिक (पुरुष, स्त्री, वायलर, पशुशाला, खेती, साधारण, लदाई और उतराई, बंडल बनाना, ढोना, उर्वरक, कटाई, प्रकीर्ण, बीजन, बुवाई, छपर छाना, प्रतिरोपण, निराई), (19) माली; (20) मजदूर (वृक्ष संवर्द्धक, कम्पोस्ट डेरी, घास का चट्टा लगाना, सिंचाई, खाद, चट्टा लगाना, दुग्धकक्ष, राशन कक्ष, भण्डार, मलेरिया-रोधक, एम० आर०); (21) संदेशवाहक (कार्यालय); (22) चपरासी; (23) सईस (24) खुली घास बांधना और ढोना; (25) स्वीपर (झाड़ूकश) (26) गांठे तोलना और ढोना; (27) तोलने वाला (गांठ, बल्ली); (28) पानी वाला; (29) तार काटने वाला; (30) तार मिस्त्री और टीन लेबल चिपकाना; (31) अस्तबल वाला; (32) ट्रोली वाला; (33) किसी भी नाम से कहलाने वाले कोई अन्य प्रवर्ग, जो अकुशल प्रकार के हैं	5.15	4.68	4.25	3.85	3.50
अर्धकुशल या अकुशल पर्यवेक्षकीय :					
(1) सहायक (चौधरी); (2) परिचारक (सांड, ब्याना-स्थल, कुट्टी मशीन, छात्रावास सुरक्षा, पशुधन, अनाज-भंडार, पम्प, रोगी पशु आवास, अस्तबल, यार्ड, पशुधन); (3) सहायक (प्लम्बर); (4) परिचारक; (5) मिस्त्री; (6) ब्रांडर; (7) खांड वाला; (8) मक्खन वाला; (9) कोचवान; (10) मोची; (11) कृषक; (12) दस्तगी; (13) पत्र-वितरक; (14) ड्रेसर, (15) फैरिअर (नाल लगाने वाला); (16) फीडर; (17) फायरमैन; (18) ग्वाला; (19) हथौड़ावाला; (20) मददगार (लोहार); (21) मददगार; (22) जमादार (सनरी); (23) जमादार; (24) खलासी; (25) माली (ज्येष्ठ); (26) मेटा मिस्त्री; (27) मजदूर (शिक्षित); (28) नालबन्द; (29) तेलावला; (30) हलवाहा; (31) चट्टा लगाने वाले; (32) पर्यवेक्षक (33) छप्पर छाने वाला; (34) तोलने वाला; (35) वाल्वमैन; (36) वाल्वमैन (ज्येष्ठ); (37) किसी भी नाम से कहलाने वाले कोई अन्य प्रवर्ग, जो अर्ध-कुशल प्रकार के हैं	6.84	6.22	5.65	5.14	4.67

1	2				
कुशल :					
(1) कारीगर (वर्ग ii, iii iv,); (2) लोहार; (3) लोहार (वर्ग ii); (4) बायलर मैन; (5) बढ़ई; (6) बढ़ई (वर्ग ii), (7) बढ़ई और लोहार; (8) चौधरी; (9) चालक (ड्राइवर), (10) चालक (ड्राइवर) (इंजन ट्रैक्टर, एम० टी०, मोटर); (11) बिजली मिस्त्री; (12) फिटर; (13) राजमिस्त्री, (14) राजमिस्त्री (वर्ग ii); (15) मशीन हैंड, वर्ग ii, iii, iv; (16) मशीन वाला, (17) मेट श्रेणी-1 (ज्येष्ठ); (18) मैकेनिक; (19) दुग्ध राइटर; (20) मिस्त्री (प्रधान); (21) खांचेवाला; (22) उपस्थिति राइटर; (23) प्रचालक (नलकूप), (24) पेन्टर; (25) प्लम्बर (नलसाज); (26) कलाईगर; (27) गद्दीवाला; (28) तारमिस्त्री (29) किसी भी नाम से कहलाने वाले कोई अन्य प्रवर्ग, जो कुशल प्रकार के है	मैट्रीकुलेट 10.25	9.32	8.47	7.70	7.00
अधिक कुशल					
(1) कारीगर वर्ग i; (2) लोहार; वर्ग i; (3) बढ़ई वर्ग i; (4) मशीन हैंड वर्ग i, (5) राजमिस्त्री, वर्ग i; (6) मैकेनिक (ज्येष्ठ); (7) किसी भी नाम से कहलाने वाले कोई अन्य प्रवर्ग, जो अधिक कुशल प्रकार के है	12.82	11.65	10.59	9.63	8.75
लिपिक वर्ग					
(1) सहायक (फार्म); (2) सहायक; (3) रोकड़िया; (4) लिपिक; (5) मुंशी; (6) रजिस्टर पाल;	10.25	9.32	8.47	7.70	7.00
(7) स्टोर कीपर (भण्डारी); (8) समय पाल (टाइमकीपर); (9) टाइपिस्ट, (10) किसी भी नाम से कहलाने वाले कोई अन्य प्रवर्ग, जो लिपिक-वर्ग प्रकार के है .	नान मैट्रिकुलेट 6.84	6.22	5.65	5.14	4.67

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

1. क्षेत्र ए, बी-1, बी-2, और सी में वे सभी स्थान समाविष्ट होंगे जो इस अधिसूचना के उपाबन्ध मे विनिर्दिष्ट है और जिसमे निगमों या नगर-पालिकाओ या छावनी बोर्डों, किसी विशिष्ट स्थान की अधिसूचित क्षेत्र समिति की परिधि से 8 किलोमीटर की दूरी के अन्दर के सभी स्थान सम्मिलित होंगे; तथा क्षेत्र डी में वे सभी स्थान समाविष्ट होंगे जो क्षेत्र ए, बी-1, बी-2, और सी के अन्तर्गत नही है।

2. जहां किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई मजदूरी कृषि में अनुसूचित नियोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा, जिसके लिए वह समुचित सरकार हो, नियत की गई मजदूरी से कम है, वहां इस अधिसूचना के अधीन न्यूनतम मजदूरी के रूप में उच्चतर दर दी जाएगी।

3. (क) **अकुशल** काम वह है जिसमें साधारण संक्रियाए आएं और जिसे करने के लिए थोड़ी सी कुशलता या अनुभव का होना या बिल्कुल ही न होना अपेक्षित हो।

(ख) **अर्ध-कुशल** : काम वह है जिसमें कुशलता या क्षमता की कुछ मात्रा आए जिसे काम पर अनुभव द्वारा प्राप्त किया जाए और जो किसी कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन में किया जा सके तथा इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षणीय काम भी है।

(ग) **कुशल** काम वह है जिसमें कुशलता या क्षमता आए जिसे काम पर अनुभव द्वारा या शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त किया जा सके और जिसके करने में पहल और विवेकबुद्धि की आवश्यकता हो।

4. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों पर भी लागू होती है।

5. मजदूरी की न्यूनतम दरों मे कुल मिलाकर सभी दरें आ जाएंगी और इसके अन्तर्गत साप्ताहिक विश्राम दिन की मजदूरी भी है।

6. नियोग्य व्यक्तियों तथा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकारो को संदेय दरो के 70 प्रतिशत के बराबर होंगी।

उपाबन्ध

नगरों/शहरो का वर्ग

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	(ए)	(बी-1)	(बी-2)	(सी)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	—	—	अदोनी, अन्काबल्ली, अनन्तपुर, बंदर (मसुलीपट्टम), भीमवरन, चिराला, चित्तूर, कुडप्पा, एलुरु, गुडीवाड़ा, गुन्ताकल, गुन्टूर, काकीनाड़ा, खम्भाम, कोठागुडम, करनूल, महबूब नगर, नंदयाल, नैल्लोर, निजामाबाद, अन्गोले, प्रोद्दतूर, राजामुन्द्री, तेनाली, तिरुपति, विजयपुरी, विजयवाड़ा (बेजवाड़ा), विशाखापटनम (विजगापट्टम), विजयनगरम, वारन्गल।

1	2	3	4	5
बिहार . . .	—	—	पटना	आरा, बेतिया, भागलपुर, बिहार, बोकारो इस्पात नगर, छपरा, दरभंगा, धानबाद, दीनापुर, गया, हजारीबाग, जमशेदपुर, कटिहार, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रांची ।
चण्डीगढ़ . . .	—	—	—	चण्डीगढ़ ।
दिल्ली . .	दिल्ली	—	—	—
गुजरात . . .	—	अहमदाबाद	सूरत बड़ोदरा (बड़ौदा)	आनन्द, भावनगर, भुज, भड़ौच, कैम्बे, धोरजी, गोधरा, गोन्दल, जामनगर, जूनागढ़, कलोल, महसाना, मोरबी, नाडियाड, नवसारी, पाटन, पोरबन्दर, राजकोट, सुरेन्द्रनगर, वेरवाल ।
हरियाणा . . .	—	—	—	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गावा, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर ।
जम्मू-कश्मीर . .	—	—	श्रीनगर	जम्मू ।
केरल . . .	—	—	कोचीन त्रिवेन्द्रम	अलेप्पी, बदगारा, कालीकट, (कोझीकोड), कन्नानोर, कयामकुलम, कोट्टायम, पालघाट, तेल्लीचेरी, त्रिचुर, क्वीलान ।
मध्य प्रदेश . .	—	—	इन्दौर, जबलपुर	भिलाई नगर–औद्योगिक नगरी, भोपाल, बिलासपुर, बुरहानपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, देवास, दुर्ग, ग्वालियर, (लश्कर), खण्डवा, मन्दसौर, मुहू (छावनी), मरवारा, रायपुर, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन ।
महाराष्ट्र . . .	मुम्बई	नागपुर, पूना	शोलापुर	अचलपुर नगर समूह, अहमदनगर, अकोला, अमलनेर, अंबरनाथ, अमरावती, औरंगाबाद, बारसी, भिवंडी, भुसावल, चांदा, चन्द्रपुर, धुलिया, दोम्बिवलि, गौंडिया, इच्छलकारंजिया, जलगांव, जालना, कल्याण, काम्बटी, खामगांव, कोल्हापुर, लातुर, मालेगांव, नांदेड़, नन्दुरबार, नासिक, नासिकरोड, देवलाली, पंढारपुर, परभणी, पिम्परी चिन्चवाड़, सांगली-मराज, सतारा, उल्हासनगर, यवतमाल, वर्धा ।
मैसूर . . .	—	बंगलौर	—	बगलकोट, बेलगांव, बेल्लारी भद्रावती, बीदार, बीजापुर, चित्र दुर्गा, दवनगीर, गादग-बेतगारी, गुलबर्गा, हसन, होसपेट, हुबली, धारवाड़, कोलार गोल्डफील्ड, मांडवा, मंगलौर, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, टुमकुर ।
उड़ीसा . . .	—	—	—	बेह्रामपुर, भुवनेश्वर, कटक, पुरी, राऊरकेला, संबलपुर,
पाण्डीचेरी . . .	—	—	—	पाण्डीचेरी ।
पंजाब . . .	—	—	अमृतसर	अबोहर, बटाला, भटिंडा, फीरोजपुर, होशियारपुर, जलन्धर, लुधियाना, मोगा, पठानकोट, पटियाला, फगवाड़ा ।
राजस्थान . . .	—	—	जयपुर	अजमेर, अलवर, बियावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जुरु, गंगानगर, जोधपुर, कोटा, सीकर, टोंक, उदयपुर ।

1	2	3	4	5
तमिलनाडु . . .	मद्रास	—	कोयम्बटूर मदुराई	अम्बूर, अरुपुक्कोटाई, बोडीनयाकानूर, कुड्डालूर, डिंडीगल, इरोड, गुडीयथम, काडयानालूर कांची-पुरम, कराईकुंडी, करूर, कुम्बकोनम, मयूरम, नागापट्टिनम, नागरकोइल, पलायमकोट्टई, पोल्लची, पुडुकोट्टई, राजापलयन, सलेम, श्रीरंगम, श्रीविल्लिपुथुर, तंबारम, थांजावुर, (तंजोर), तिरुचिरापल्ली (त्रिचनापल्ली) तिरुनेलवेली, तिरुपुरा, तिरुवन्नमलाई, तूतीकोरिन, वालपराई, वनियमबोडी, वेल्लूर, विल्लीपुरम, विरुथुनगर ।
उत्तर प्रदेश . . .	—	कानपुर, लखनऊ	आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी (बनारस)	अलीगढ़ (कोल अलीगढ़), अमरोहा, बहराइच, बांदा, बरेली, बदायूं, बुलन्दशहर, चदौसी, देहरादून, इटावा, फैजाबाद एवं अयोध्या, फरुखाबाद एवं, फतेहगढ़, फतेहपुर, फीरोजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हल्द्वानी, एव काठगोदाम, हापुड़, हरिद्वार, हाथरस, जौनपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुज्जफरनगर, पीलीभीत, रामपुर, रुड़की, सहारनपुर, संभल, शाहजहांपुर, सीतापुर ।
पश्चिम बंगाल . .	कलकत्ता	—	—	आसनसोल, वैद्यवाटी, बाल्ली, बनगाव, बांकुरा बागबेरिया, बैरकपुर, बसीरहाट, बेरहामपुर, भाटपाड़ा, बुज बुज, बर्दवान, चमनदानी, चन्द्र नगर, कूच बिहार, दुर्गापुर, इंगलिश बाजार, हालीशहर, हुगली, चिन्सुरा, जलपाईगुड़ी, कमर-हटी, कंचरा-पाड़ा, खड्गपुर, कृष्णानगर, मिदना-पुर, नवाद्वीप, नईहाटी, नार्थडन डन, पनिहाटी, पुरलिया, रिशरा, शान्तिपुर, सेरमपुर, सिलीगुड़ी, टीटागढ़, उत्तर पुरा, कोटरग ।

[सं० एम-32019(8)/72-डब्ल्यु ई (एम डब्ल्यु)]

हंसराज छाबड़ा, उप-सचिव

S.O. 2389.—Whereas certain proposals to revise minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in the mployment in agriculture were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), on pages 4693 to 4698 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th October, 1972, under the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), S.O. 3221, dated the 25th August, 1972, for information for, and inviting objections, suggestions or representations from, all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of three months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And Whereas the said Gazette was made available to the Public on the 28th October, 1972.

And Whereas all the objections, suggestions and representations received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (i) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of all the notifications issued on the subject, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employment in agriculture as specified in the corresponding entries in column 1 of the said Schedule and directs that this notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Categories of employees	All inclusive minimum rates of wages per day.				
	Area A	Area B1	Area B2	Area C	Area D
	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
1			2		
Unskilled:					
(1) Beldar (Male/Female); (2) Calf Boy; (3) Cattleman; (4) Chowkidar; (5) Cleaner, (6) Cleaner (Motor shed; Tractor; Cattle Yard; M.T.); (7) Collecting Loose fodder; (8) Dhobi; (9) Dairy Coolies; (10) Dairy-man; (11) Dismantling Stocks; (12) Dresser; (13) Driver (Bullocks; Mule); (14) Feeder (Adult) Hay; (15) Grass Cutter; (16) Grazier; (17) Helper (Store-Mazdoor); (18) Labourer (Male; Female; Boiler; Cattle Yard; Cultivation; General; Loading and Unloading; Bundling; Carting, Fertilizers; Harvesting; Miscellaneous; Seeding; Sowing; Thatching; Transplanting; Weeding), (19) Mali; (20) Mazdoor (Arboriculturist; Compost; Dairy; Hay-Stacking; Irrigation, manure; Stacking; Milk Room; Ration Room; Store; Anti-Malatia; M.R.); (21) Messenger (Office); (22) Peon; (23) Syce; (24) Tying & Carrying Loose Hay; (25) Sweeper; (26) Weighing and Carrying Bales; (27) Weighman Bales; Pally); (28) Waterman; (29) Wire-Cutter; (30) Wireman and Fixing Tin Lebels; (31) Stable Man; (32) Trolly Man; (33) Any other categories by whatever name called which are of unskilled nature.	5.15	4.68	4.25	3.85	3.50
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory:					
(1) Assistant (Chowdnary); (2) Attendant (Bull; Calving Line; Chaff Cutter; Hostel; Dry Stock; Grain Crusher; Pump; Sickline; Stable; Yard; Stock), (3) Assistant (Plumber); (4) Attendant; (5) Bhisti; (6) Brander; (7) Bullman; (8) Butterman; (9) Coachman; (10) Cobbler; (11) Cultivator; (12) Daftry; (13) Delivery Man; (14) Dresser; (15) Farriar; (16) Feeders; (17) Fireman; (18) Gowalas; (19) Hammerman (20) Helper (Blacksmith); (21) Helper; (22) Jamadar (Stand); (23) Jamadar; (24) Khalasi; (25) Mali (Senior; (26) Mate/Mistry; (27) Mazdoor (Literate); (28) Nalband; (29) Oilman: (30) Ploughman; (31) Stackers; (32) Supervisor; (33) Thatcher; (34) Weighman; (35) Valveman; (36) Valveman (Senior); (37) Any other categories by whatever name called which are of a semi-skilled nature . . .	6.84	6.22	5.65	5.14	4.67
Skilled:					
(1) Artificier (Class II; III; IV); (2) Blacksmith; (3) Blacksmith (Class II); (4) Boiler Man; (5) Carpenter; (6) Carpenter Class II; (7) Carpenter-cum-Blacksmith; (8) Chowdhary; (9) Driver; (10) Driver (Engine Tractor; M.T.; Motor); (11) Electrician; (12) Fitter; (13) Mason; (14) Mason Class II; (15) Machine hand (Class II, III, IV) (16) Machineman; (17) Mate Gr. I (Senior); (18) Mechanic; (19) Milk Writer; (20) Mistry (Head); (21) Moulder; (22) Muster Writer; (23) Operator (Tube-well); (24) Painter; (25) Plumber; (26) Welder; (27) Upholsterer (28) Wireman; (29) Any other categories by whatever name called which are of a skilled nature	10.25	9.32	8 47	7.70	7.00
Highly Skilled:					
(1) Artificier, ClassI; (2) Blacksmith Class I; (3) Carpenter Class I, (4) Machine Hand Class I, (5) Mason Class I; (6) Mechanic (Senior); (7) Any other categories by whatever name Called which are of highly skilled nature	12.82	11.65	10.59	9.63	8.75
Clerical:					
(1) Assistant (Farm); (2) Assistant; (3) Cashier; (4) Clerk; (5) Munshi; (6) Register-Keeper; (7) Storekeeper; (8) Timekeeper; (9) Typist; (10) Any other categories by whatever name called which are of a clerical nature	10.25	9.32	Matriculates 8.47	7.70	7.00
	6.84	6.22	Non-Matriculates 5.65	5.14	4.67

EXPLANATIONS: For purposes of this notification:—

1. Areas A, B-1, B-2 and C shall comprise of all the places as specified in the Annexure to this notification including all places within a distance of 8 Kilometre from the periphery of the Corporation or Municipalities or Cantonment Boards, Notified Area Committee of a Particular place; and Area D shall comprise of all the places not included in Areas A-1, B-1 B-2 and C.

2. Where in any area the wages fixed under this notification are lower than the wages fixed by the State Government for the scheduled employment in Agriculture for which it is the appropriate Government, the higher rate would be payable as minimum wage under this notification.

3. (a) **Unskilled** work in one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) **Semi-skilled** work is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work.

(c) **Skilled** work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

4. The minimum rates of wages are applicable to employees engaged by contractors also.

5. The minimum rates of wages shall consist of an all inclusive rates, and include also the wages for weekly day of rest.

6. The minimum rates of wages for disabled and young persons below 18 years of age shall be 70% of the rates paybale to adult workers of the appropriate category.

ANNEXURE

Name of the State	Class of Cities/Towns			
	'A'	'B-1'	'B'-2'	'C'
1	2	3	4	5
Andhra Pradesh	Hyderabad	...	...	Adoni, Anakapalle, Anantapur, Bandar (Muslipatam), Bheemavaram, Chairala, Chittoor, Cuddapah, Eluru, Gudivada, Guntakkal, Guntur, Kakinada Khammam, Kothagudem, Kurnool, Mahbubnagar, Nandyal, Nellore, Nizamabad, Ongole, Proddatur, Rajamuddry, Tenali, Tirupati, Vijayapuri, Vijayawada (Bezwada), Visakhapatnam (Vizagapatam), Vizianagaram, Warangal.
Bihar	...	...	Patna	Arrah, Bettiah, Bhagalpur, Bihar, Bokaro, Steel City Chapra, Darbhanga, Dhanbad, Dinapur, Gaya, Hazribagh, Jamshedpur, Katihar, Monghyr-Jamalpur, Muzaffarpur, Purnea, Ranchi.
Chandigarh	...	...	...	Chandigarh.
Delhi	Delhi	...	...	...
Gujarat	...	Ahmedabad	Surat, Vadodara (Baroda)	Anand, Dhavnagar, Bhuj, Broach, Cambay, Dhoraji, Godhra, Gondal, Jamnagar, Junagadh, Kalol, Mahesana, Morvi, Nadiad, Navsari, Patan, Porbandar, Rajkot, Surendranagar, Veraval.
Haryana	...	...	...	Ambala, Bhiwani, Faridabad, Gurgaon, Hissar, Karnal Panipat, Rohtak, Sonepat, Yamunanagar.
Jammu & Kashmir	...	...	Srinagar	Jammu.
Kerala	...	...	Cochin, Trivandrum	Alleppey, Badagara, Calicut (Kozhikode), Cannanore, Kayamkulam, Kottayam, Palghat, Tellicherry, Trichur, Quilon.
Madhya Pradesh	...	...	Indore, Jabalpur	Bhilainagar, Industrial Township, Bhopal, Bilaspur, Burhanpur, Chhindwara, Damoh, Dewas, Drug, Gwalior (Lashkar), Khandwa, Mandsaur, Mhow (Cantt.), Murwara, Raipur, Ratlam, Rewa, Sagar, Satna, Ujjain.
Maharashtra	Bombay	Nagpur, Poona	Sholapur	Achalpur Town group, Ahmednagar, Akola, Amalner, Ambarnath, Amravati, Aurangabad, Barsi, Bhivanji, Bhusawal, Chanda, Chandrapur, Dhulia, Dombivli, Gondia, Ichalkaranjia, Jalgaon, Jalna, Kalyan, Kamptee, Khamgaon, Kolhapur, Latur, Malegaon, Nanded, Nandurbar, Nasik, Nasik Road, Deolali, Pandharpur, Parbhani, Pimpri-Chinchwad, Sangli-Maraj, Satara, Vihasnagar Yeotmal, Wardha.
Mysore	...	Bangalore	...	Bagalkot, Belgaum, Bellary, Bhadravati, Bidar, Bijapur, Chitradurga, Davangere, Gadag-Betgari, Gulbarga, Hassan, Hospet, Hubli-Dharwar, Kolar Gold Fields, Mandya, Mangalore, Mysore, Raichur, Shimoga, Tumkur.
Orissa	...	...	...	Behrampur, Bhubaneswar, Cuttack, Puri, Rourkela, Sambalpur.
Pondicherry	...	...	...	Pondicherry.
Punjab	...	...	Amritsar	Abohar, Batala, Bhatinda, Ferozepur, Hoshiarpur, Jullundur, Ludhiana, Moga, Pathankot, Patiala, Phagwara.
Rajasthan	...	...	Jaipur	Ajmer, Alwar, Beawar, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, Chury, Ganganagar, Jodhpur, Kota, Sikar, Tonk, Udaipur.
Tamil Nadu	Madras	...	Coimbatore Madurai	Ambur, Aruppukkottai, Bodinaya-Ranur, Cuddalore, Dindigul, Erode, Gudiyatham, Kadyanallur, Kancheepuram, Karaikudi, Karur, Kumbakonam, Mayuram, Nagapattina Nagercoil, Palayamcottai, Pollachi, Pudukkottai, Rajapalayam, Salem, Srirangam, Srivilliputtur, Tambaram, Thanjavur, (Thanjore), Tiruchirapalli (Trichinopoly), Tirunelveli, Tiruppur, Tiruvannamalai, Tuticorin, Valparai, Vaniyambodi, Vellore, Villipuram, Virudhunagar.

1	2	3	4	5
Uttar Pradesh	...	Kanpur, Lucknow	Agra, Allahabad Varanasi (Banaras)	Aligarh, (Koil Aligarh), Amroha Baharaich, Banda, Bareilly, Budaun, Bulandshahar, Chandausi, Dehra Dun, Etawah, Faizabad-cum-Ayodhya, Farrukhabad.-cum-Fatehgarh, Fatehpur, Firozabad-Ghaziabad, Gonda, Gorakhpur, Haldwani-cum-Kathogodam, Hapur, Hardwar, Hathras, Jaunt pur, Mirzapur, Moradabad, Muzaffarnagar, Pilibhin-Rampur, Roorkee, Saharanpur, Sambhal, Shahjah a pur, Sitapur.
West Bengal	Calcutta	...	..	Asansol, Baidyabati, Bally, Bangaon, Bankura, Bans baria, Barrackpur, Basirhat, Berhampur, Bhatpara Budge Budge, Burdwan, Champdani, Chandernagore, Cooch Behar, Durgapur, English Bazar, Halishahar,, Hooghly, Chinsura, Jalpaiguri, Kamarhati, Kancha para, Kharagpur, Krishnaga r, Midnapur, Nabadwip, Naihati, North Dum Dum, Panihati, Purulia, Rishra, Santipur, Serampur, Siliguri, Titagarh, Uttarpara-Kotrung.

[No. S-32019/(8)/72-WE (M.W.)

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

का० आ० 2390—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय तेल निगम, लिमिटेड के गोहाटी प्रतिष्ठान और पटना प्रतिष्ठान को उक्त नियम के प्रवर्तन से, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 27 जून, 1971 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, छूट देती है।

[फा० सं० एस० 38017(1)/73-एच आई]

दलजीत सिंह, अवर सचिव

S.O. 2390.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the Gauhati installation and Patna Installation of the Indian Oil Corporation Limited from the operation of the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette upto and inclusive of the 27th June, 1974.

[File No. S. 38017(1)/73-HI]

DALJIT SINGH, Under Secy.

मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली 6 अगस्त, 1973

का० आ० 2391—यत मेसर्स तन्दूर एंड नवन्दगी स्टोन क्वारीज प्राईवेट लिमिटेड (नियोजक) ने नीचे की अनुसूचित में वर्णित अपने स्थापनों के संबंध में 30-9-1972 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को बोनस के संदाय की कालावधि को बढ़ाने के लिए बोनस सदाय अधिनियम, 1965 की धारा 19(ख) के अधीन आवेदन दिया है ।

और यत, यह समाधान हो जाने पर कि समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण है, मैंने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० डब्ल्यू बी-20(12)/65 तारीख 28 अगस्त, 1965 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 के खंड (ख) के परन्तुक द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26-7-1973 को उक्त नियोजक द्वारा उक्त बोनस के संदाय की कालावधि को अधिनियम की धारा 19 के खंड (ख) के अधीन बोनस के सदाय की अंतिम तारीख से 3 महिने (अर्थात 31-8-1973 तक) बढ़ाने का आदेश दे दिया है ।

अब इसे उक्त स्थापन के नियोजक और सभी कर्मचारियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

अनुसूची

नियोजक/नियोजकों का नाम और पता	स्थापन
मेसर्स तन्दूर एंड नवन्दगी एस्टोन क्वारीज प्रा० लि० पो० ओ० वशीराबाद नवन्दगी, एम०सी० रेलवे जिला हैदराबाद (ए०पी०)	आर० जे० टी० डी'मेलो, तन० स्टोन क्वा० प० लि०

[एम०बी० ए 16 (14)/73 एस एस 1]

मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)

Office of the Chief Labour Commissioner(Central)

ORDER

New Delhi, the 6th August, 1973

S.O. 2391.—Whereas an application has been made under section 19(b) of the Payment of Bonus Act, 1965 by Messrs Tandur & Navandgi Stone Quarries Pvt. Ltd. (employer) in relation to their establishments mentioned in the Schedule below for extension of the period for the payment of bonus to their employees for the accounting year ending on 30-9-1972.

And whereas being satisfied that there are sufficient reasons to extend the time I have, in exercise of the powers conferred on me by the proviso to clause (b) of Section 19 of the said Act read with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. WB. 20(42)/65 dated the 28th August, 1965, passed order on 26-7-1973 extending the period for payment of the said bonus by the said employer by 3 months (i.e. up to 31-8-1973) from the last date for payment of bonus under clause (b) of Section 19 of the Act.

Now this is published for information of the employer and all the employees of the said establishment.

The Schedule

Name and address of the employer(s).	Establishment(s)
M/s. Tandur & Navandgi Stone Quarries Pvt. Ltd., P.O. Bashirabad Navandgi, S.C. Rly., Distt. Hyderabad A.P.	The Tandur & Navandgi Stone Quarries Pvt. Ltd., 79, Marredpelly, (Nehru Nagar) Secunderabad A.P.

[No. BA-16(14)/73-LS. I]

R. J. T. D'MELLO,
Chief Labour Commissioner (Central).

पुनर्वास विभाग

नई दिल्ली-11, 7 अगस्त, 1973

का० आ० 2392—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी श्री डी० सी० चौधरी को मुआवजा भंडार की अभिरक्षा, प्रबन्ध तथा निपटान के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों के लिए प्रबन्ध अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 28(201)/आर एस सी डी/एडमन/65]

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 7th August, 1973

S.O. 2392.—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub-section (2) of Section 16 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) the Central Government hereby appoints Shri D. C. Chaudhry, Assistant Settlement Officer in the office of the Regional Settlement Commisioner (Central) as Managing Officer for the custody, management and disposal of compensation pool for the States of Uttar Pradesh, Bihar, Orissa, Rajasthan and Madhya Pradesh.

[No. 28(201)/RSCD/Admn/65.]

का० आ० 2393—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी श्री डी० सी० चौधरी को उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत सहायक अभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों के लिए सहायक अभिरक्षक, निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 28(201)/आर एस सी डी/एडमन/65]

डी० एन० असीजा, अवर सचिव,

S.O. 2393.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950, the Central Government hereby appoints for the States of Uttar Pradesh, Bihar, Orissa, Rajasthan and Madhya Pradesh, Shri D. C. Chaudhry, Assistant Settlement Officer in the Office of the Regional Settlement Commissioner (Central) as Assistant Custodian of Evacuee Property for the purpose of discharging the duties assigned to Asstt. Custodians by or under the said Act.

[No. 28(201)/RSCD/Admn /65]

D. N. ASIJA, Under Secy.

औद्योगिक विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1973

का. आ. 2394.—विकास परिषद् (प्रक्रिया संबंधी) नियम, 1952 के नियम 8 के साथ पठित, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, स्वर्गीय डा. ए. जी. सीनार के स्थान पर श्री राजा कुलकर्णी, संसद्-सदस्य, 19, जनपथ-1, नई दिल्ली, को 12 सितम्बर, 1973 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए औषधि तथा भेषज उद्योग विकास परिषद् का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3499/उ. वि. वि. अ./(/11/71, तारीख 13 सितम्बर, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के पैरा 1 में क्रम सं. 23 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"23. श्री राजा कुलकर्णी, संसद्-सदस्य, 19, जनपथ-1, नई दिल्ली।"

[सं. 13(7)/70-एल सी]

आर. बी. माथुर, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, SCIENCE AND TECHNOLOGY

ORDER

New Delhi, the 9th August, 1973

S.O. 2394.—IDRA/6/73.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rule 8 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints Shri Raja Kulkarni, M. P., 19, Janpath-1, New Delhi, in place of late Dr. A. G. Senar, as a member of the Development Council for Drugs and Pharmaceutical Industries, for a period upto and inclusive of the 12th September, 1973, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Developmnt No. S.O. 3499/IDRA/6/11/71 dated the 13th September, 1971, namely:—

In paragraph 1 of the said Order, for serial No. 23 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"23. Shri Raja Kulkarni, M.P., 19, Janpath-1, New Delhi."

[No. 13(7)/70-LC.]

R. B. MATHUR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1973

~~142/TCD 72/CSL~~

195/IOD-73/CSL